जनवरी-फरवरी-मार्च, 2026, वर्ष 34, अंक 11

उत्तर प्रदेश

संदेश

समृद्ध उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था

बजट 2026-27

राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों में यूपी का अंश

₹3.34 लाख करोड़

(अनुमानित)

2026-27

GSDP में तीव्र वृद्धि

GDP की वृद्धि दर

13.4%

2024-25

आमदनी हुई दोगुनी

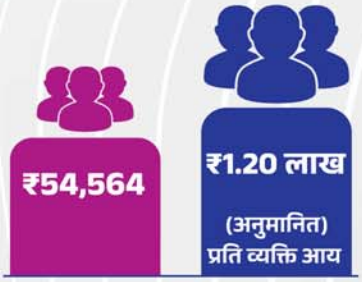

2016-17 2025-26

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

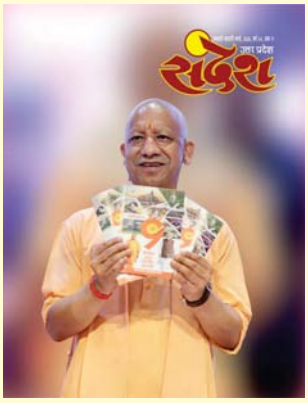

जनवरी-फरवरी-मार्च, 2026, वर्ष 34, अंक 11

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

❖

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
विशाल सिंह
सूचना निदेशक

❖

सम्पादकीय परामर्श :
अरविन्द कुमार मिश्र
अपर निदेशक, सूचना

❖

चन्द्र विजय वर्मा
सहायक निदेशक (प्रकाशन)

❖

दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

❖

अजय कुमार द्विवेदी
सहयुक्त संपादक

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9919874392, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- नव निर्माण के नौ वर्ष : योगी सरकार का... 3
  –अनिल श्रीवास्तव
- उत्तर प्रदेश की स्थापना का जनोत्सव 7
  –सियाराम पांडेय 'शांत'
- यूपी में सरपट दौड़ रहा विकास का पहिया 13
  –यशोदा श्रीवास्तव
- विकसित उत्तर प्रदेश का बजट 16
  –प्रमोद शुक्ला
- राष्ट्र-निर्माण की पाठशाला : राष्ट्र प्रेरणा स्थल 20
  –शिवानी कटारा
- पीठासीन अधिकारियों का महासंगम 24
  –राधिका
- जेवर एयरपोर्ट : विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान 30
  –डॉ. सौरभ मालवीय
- एआई सिटी और भविष्य का उत्तर प्रदेश 36
  –डॉ. ऋतु दुबे तिवारी
- रक्षा उत्पादन केंद्र बनता उत्तर प्रदेश 38
  –प्रदीप कुमार गुप्ता
- आत्मनिर्भर होता ग्रामीण उत्तर प्रदेश 43
  –डॉ. शिव राम पाण्डेय
- यूपी पुलिस दुनिया के लिए रोल मॉडल 48
  –राघवेंद्र प्रताप सिंह
- डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता 53
  –डॉ. दीपक कोहली
- नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का मिशन 57
  –सुनील सिंह
- हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम 60
  –पवन सिंह
- यूपी में अनवरत होते पुलिस सुधार 62
  –उपेन्द्र कुमार

सम्पादकीय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का दौरा कई मायनों में खास रहा। इस यात्रा में यूपी को आर्थिक मजबूती के लिए दोनों देशों से निवेश की दरकार तो थी ही लेकिन बुद्ध से बुद्ध तक के आत्मीय रिश्ते की डोर को मजबूत करना सीएम योगी की यात्रा की बड़ी कामयाबी है। वह भी इतने सलीके से कि बिना किसी बौद्ध धर्म गुरु से मिले, दोनों देशों के बुद्ध अनुयायियों को अपना बना आए। बता दें कि बौद्ध तीर्थ स्थलों में यूपी का खास महत्व है। यहां सिद्धार्थनगर जिले में राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु (पिपरहवा) स्थित है। बौद्ध अनुयायियों का यह बड़ा और अति महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। गौतम बुद्ध ने यहां अपने जीवन के 29 साल बिताए। यहीं से राजसुख त्याग कर उन्होंने बौद्ध भिक्षु की अपनी आगे की जीवन यात्रा प्रारम्भ की जिसके ढेर सारे पड़ाव हैं। इसमें सारनाथ भी है, बौद्ध गया, श्रावस्ती, देवदह, कुशीनगर आदि शामिल है। इन सभी स्थलों के अपने-अपने महत्व हैं। सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल के रूप में जाना जाता है, कुशीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और बौद्ध गया को बुद्ध की ज्ञानार्जन स्थली के रूप में जाना जाता है। बौद्ध गया बिहार में है लेकिन बुद्ध से जुड़े ज्यादातर स्थल यूपी में है।

जापान की राजधानी टोकियो में योगी आदित्यनाथ ने इन सभी बौद्ध स्थलों के बारे में विस्तार से वर्णन कर बुद्ध के अनुयायियों के देश में लोगों को सम्मोहित किया। मुख्यमंत्री योगी ने सिंगापुर और जापान में उद्योगपतियों, बड़े व्यवसायियों और निवेशकों की मीटिंग में भारत और खासकर यूपी के प्रमुख बौद्ध स्थलों के महत्व को बताते हुए भारत से सिंगापुर और जापान से धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को रेखांकित किया। बुद्ध के अनुयायियों की दृष्टि से जापान और सिंगापुर बड़ी आबादी वाला देश है। सिंगापुर में करीब 32 प्रतिशत की आबादी बुद्धिस्ट है जो बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीनी मूल के हैं जो महायान परंपरा का निर्वहन करते हैं। जापान में भी बौद्ध अनुयायियों का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है। यहां कुल आबादी का लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या बुद्ध की अनुयायी है। इनमें से तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिंटो और बौद्ध दोनों धर्मों को मानते हैं। यह जापान के मुख्य धर्मों में से एक है। शिंटो धर्म के अनुयायी अंतिम संस्कार में बौद्ध धर्म का पालन करते हैं।

निश्चित ही यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य के लिए मुख्यमंत्री योगी का बुद्ध के अनुयायी दोनों देशों का दौरा शानदार रहा। मुख्यमंत्री चाहे सिंगापुर हो या जापान, दोनों देशों में जब पर्यटन विकास की बात करते हैं तो उसमें यूपी के बुद्ध स्थलों का विकास स्वत: जुड़ा हुआ होता है। मुख्यमंत्री का दोनों देशों की यात्रा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी की दृष्टि से एक सफलतम यात्रा रही। मुख्यमंत्री योगी के निकटवर्ती लोगों का कहना है कि सिंगापुर और जापान का दौरा उनकी दूरदृष्टि और नियोजित विकास की सोच का उदाहरण है। इस दौरे के पहले यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पांच सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण जापानी इंडस्ट्री निवेश के लिए ही किया था। इस भू-भाग पर जापान से जो हजारों करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, उसका उपयोग विभिन्न कंपनियों और उद्योग की स्थापना के लिए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास फिलहाल यूपी के युवकों के लिए वरदान है जिन्हें अब रोजगार के लिए दूसरे देशों की ओर नहीं ताकना होगा।

लोगों की मानें तो इस एक दौरे से सिंगापुर और जापान के लोगों में योगी उसी तरह स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं जैसे नेपाल के लोगों में। गोरक्षपीठ जिसके महंत योगी जी हैं, इसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में अपना प्रभाव स्थापित किया है। नेपाल में लाखों लोग हैं जो गोरखनाथ मंदिर के प्रति आस्थावान हैं। राजशाही के जमाने से मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में चढ़ावे के लिए पहली खिचड़ी नेपाल के राजा की आती थी। नेपाल में राजशाही भले न हो, आज भी पहली खिचड़ी राजपरिवार से ही आती है। नेपाल में योगी की पहचान हिंदू रक्षक के रूप में है। नेपाल हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है,ऐसे में नेपाल का हिंदू जनमानस योगी आदित्यनाथ को अपना संरक्षक मानता है।

बौद्ध धर्म नि:संदेह हिंदू धर्म का ही एक अंग है। सिंगापुर और जापान में योगी ने जिस तरह बौद्ध धर्म के माहात्म्य की व्याख्या की है उससे भगवान बुद्ध को मानने वाली दुनिया के दो बड़े देशों में योगी ने खुद को स्थापित करने में भी सफलता हासिल की है।

सम्पादक

नव निर्माण के नौ वर्ष : योगी सरकार का अभूतपूर्व विकास मॉडल

—अनिल श्रीवास्तव

बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुशासन और सुरक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश को बढ़ावा देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के मामले में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा, विकास और सुशासन का प्रतीक बन गया है। कभी चुनौतियों के लिए पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह नौ वर्षों की यात्रा केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं, बल्कि 'नए उत्तर प्रदेश?' के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने का सशक्त उदाहरण भी है। आज उत्तर प्रदेश एक उभरती आर्थिक शक्ति, मजबूत कानून–व्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले राज्य के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है। उत्तर प्रदेश अब 'विकसित भारत/2047' का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने की राह पर है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 मार्च, 2026 को अपने नौ वर्ष पूरे कर लिए। यह वह समय है जब कभी 'बेबस, भ्रष्ट और अराजक' माना जाने वाला उत्तर प्रदेश 'सुरक्षा, विकास और सुशासन' का नया मॉडल बनकर उभरा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक कार्य किए हैं। नौ वर्ष पहले 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब प्रदेश दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार और निवेश की कमी की मार झेल रहा था। आज स्थिति उलट है। कानून–व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र में ठोस प्रगति दिख रही है। यह उपलब्धियां केवल आंकड़ों में ही नहीं हैं, बल्कि आम जनता के जीवन में महसूस की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून–व्यवस्था में सुधार है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का नया मॉडल तैयार

हुआ। पूर्व की सरकारों में दंगे, माफिया राज और महिलाओं पर अत्याचार आम थे। योगी सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई। गैंगस्टरों और माफिया पर सख्त कार्रवाई हुई, अवैध कब्जे हटाए गए और जबरन वसूली के नेटवर्क तोड़े गए, जिससे आम लोगों ने काफी राहत महसूस की। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन और मंडल स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गईं।

मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स ने डिजिटल अपराधों में तेजी से कार्रवाई संभव बनाई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस में 2.19 लाख नई भर्तियां की गईं। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सात प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया। साथ ही, पीएसी की 34 कंपनियों को सक्रिय किया गया और पहली बार महिला बटालियन का गठन भी किया गया। परिणामस्वरूप प्रदेश 'दंगा–मुक्त' हुआ और निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार हुआ। इसका नतीजा आज सामने है भी। उत्तर प्रदेश आज निवेशकों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बन चुका है और बड़े पैमाने पर निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में लगातार हो रही वृद्धि बेहतर कानून–व्यवस्था का ही परिणाम है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 मार्च, 2026 को अपने नौ वर्ष पूरे कर लिए। यह वह समय है जब कभी 'बेबस, भ्रष्ट और अराजक' माना जाने वाला उत्तर प्रदेश 'सुरक्षा, विकास और सुशासन' का नया मॉडल बनकर उभरा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, किसानों के कल्याण, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक कार्य किए हैं।

आधारभूत संरचना के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बीते नौ वर्षों में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक्सप्रेस–वे और एयरपोर्ट क्रांति के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज देश का लीडर बन गया है। भारत के कुल एक्सप्रेस–वे नेटवर्क का लगभग 95: हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। गंगा एक्सप्रेस–वे पूर्ण होने की कगार पर है, जबकि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य एक्सप्रेस–वे ने कनेक्टिविटी को काफी सुगम और तीव्र बना दिया है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सड़क नेटवर्क ने लॉजिस्टिक्स लागत कम की है। एयरपोर्ट क्रांति भी कम उल्लेखनीय नहीं। नौ वर्षों में 4 अंतरराष्ट्रीय सहित 16 एयरपोर्ट परिचालन में आ गए। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे

बड़ा रेल नेटवर्क भी है। इन परियोजनाओं ने न केवल रोजगार सृजन किया, बल्कि प्रदेश को 'लॉजिस्टिक्स हब' बना दिया।

एक समय था जब उत्तर प्रदेश 'बीमारू राज्य' कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। राज्य की अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़ गई है। प्रदेश को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट जैसी परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, जिसने उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और AI में निवेश बढ़ा है। 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना ने स्थानीय उद्योगों को मजबूत किया। 2026–27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट तैयार किया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति और लैंड बैंक ने निवेशकों का भरोसा जीता। योगी सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य को 'विकसित उत्तर प्रदेश' के रूप में स्थापित करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना है। योगी सरकार की प्रभावी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करके युवाओं के सपनों को साकार करने की बड़ी पहल की। योगी सरकार में बीते नौ वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं, जिसमें 2.19 लाख पुलिस की भर्तियां शामिल हैं। महिलाओं को 1.75 लाख सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और ODOP जैसी योजनाएं रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो गन्ना किसानों को समय से भुगतान और किसानों की आय बढ़ाने पर योगी सरकार का विशेष जोर रहा। गन्ना किसानों को 2017 से अब तक 3.16 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद, सिंचाई विस्तार, मंडी फीस में कमी और निजी ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं दी गईं। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ और किसान संकट से उबरे। कृषि एवं किसान केंद्रित योगी सरकार की योजनाओं का असर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ नजर आ रहा है। सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण केंद्रित योजनाएं 'आखिरी पायदान' तक पहुंचीं। लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 62 लाख से अधिक घर दिए गए हैं। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) से बिचौलियों को हटाया गया, जिससे योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का रास्ता साफ हुआ है। प्रदेश में 80,000 उचित मूल्य दुकानों को ई–पीओएस से जोड़ा गया, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। लगभग 1.10 करोड़

महिलाएं स्वयं–सहायता समूहों से जुड़ीं। कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में लाखों लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जल जीवन मिशन और हर घर नल से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। दलितों और पिछड़ों के लिए लक्षित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिससे समाज के दबे–कुचले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नीतिगत प्रयासों के कारण लाखों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

योगी सरकार का जोर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी चुस्त–दुरुस्त करने पर रहा है। लगभग 6 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया गया, एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियां नियंत्रित हुईं। शिक्षा में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत 1.36 लाख स्कूल अपग्रेड किए गए। 1.6 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म और पुस्तकें दी गईं, ड्रॉपआउट दर शून्य हुई। पर्यावरण के लिए बड़े पौधरोपण अभियान चलाए गए। धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक पर्यटन सर्किट ने सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक विकास किया। काशी विश्वनाथ धाम, विंध्याचल धाम और श्री राम मंदिर जैसी बड़ी परियोजनाओं के बाद उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। प्रदेश में देशी–विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नौ वर्षों की यह यात्रा 'ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी' पर आधारित रही। योगी सरकार अब युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और 2047 तक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर और ज्यादा तेजी से फोकस कर रही है। नौ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 'जन चर्चा' बनाने के लिए नौ दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें युवा, किसान, महिलाएं और उद्योग शामिल हैं। यह केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि आम आदमी की बदलती जिंदगी की कहानी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की साझेदारी ने उत्तर प्रदेश को 'नए भारत' का प्रतीक बना दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साबित किया कि मजबूत इच्छाशक्ति, ईमानदार नेतृत्व और जन–समर्थन से कोई भी राज्य बदल सकता है। यह नौ वर्ष 'नव निर्माण' के हैं। आने वाले वर्षों में यह मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ◆

मो. : 9935097410

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

उत्तर प्रदेश की स्थापना का जनोत्सव

–सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को जनोत्सव के रूप में मनाया गया। इसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों की सक्रिय सहभागिता रही। व्यक्ति का जन्म दिवस हो या संस्थाओं का स्थापना दिवस, उसका महत्व ही अलग है। जिस दिन उत्तर प्रदेश को अपना नाम मिला हो, उस दिन की अहमियत की कल्पना सहज ही की जा सकती है। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन यूं तो उसके स्थापना दिवस न सही, आजादी के बाद से ही आरंभ हो जाना चाहिए था लेकिन जब जागे तभी सबेरा। वर्ष 2018 से यह आयोजन साल दर साल हो रहा है। अलग–अलग थीम पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हर स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य को कोई न कोई बड़ी योजना देते रहे हैं।

पहले स्थापना दिवस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक जिला–एक उत्पाद योजना आरंभ की थी। दूसरे स्थापना दिवस पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू हुई थी। इस साल उन्होंने एक जिला–एक व्यंजन योजना आरंभ की है। 24 से 26 जनवरी तक चले इस विशेष आयोजन में लोगों को उत्तर प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को एक मंच पर देखने और जानने–समझने का अवसर मिला। लोगों को सम्मेलन में सांस्कृतिक विविधता के साथ ही विकास की समवेत चेतना के भी दीदार हुए। अंतरिक्ष यात्री एवं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले अलख पांडेय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले डॉ. हरिओम पंवार, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमद् दयानंद आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना करने वाली रश्मि आर्य और कृषि क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉ. सुधांशु सिंह को उप्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इन हस्तियों ने इस दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रौशन किया है।

उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को देश की आत्मा करार दिया और कहा उत्तर प्रदेश भारत की धड़कन

है, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन बनेगा, एक विकसित भारत का इंजन। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी डबल–इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को भी एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। हम सभी आज इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त, 2047 को स्वतंत्रता की शताब्दी मनाई जाएगी, तब उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य होगा और एक विकसित भारत का महत्वपूर्ण राज्य बनेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में कानून–व्यवस्था की स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, जिससे निवेश आकर्षित हुआ और विकास में तेजी आई। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों का एक व्यापक नेटवर्क प्रदान किया है और ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश में बन रही है। यह बदलाव इसलिए संभव हो सका क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने संकल्प के साथ भ्रष्टाचार को खत्म किया, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कीं, और यह सुनिश्चित किया कि हर गांव में कम से कम 20 घंटे बिजली आपूर्ति हो। शहरी परिवर्तन को भी रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि 65 एकड़ का कूड़ाघर अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में एक स्वच्छ और उपयोगी सार्वजनिक स्थान में परिवर्तित हो चुका है। सफाई पहलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया, जिससे राज्य भर में नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार को प्रदर्शित किया गया। युवाओं को पांच लाख रुपये तक के ब्याज–मुक्त और कुछ गिरवी रखकर मिलने वाले ऋणों का लाभ मिला है, जिसके लिए अब तक 5,322 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

एक जिला, एक उत्पाद योजना युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन चुकी है, साथ ही यह उत्तर प्रदेश के पारंपरिक खाद्य पदार्थों व उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश अब देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, यह भारत का खाद्य कटोरा बन गया है, एथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर है, और कृषि, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, साथ ही 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लागू किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और

प्रयागराज में महाकुंभ जैसे आयोजन भारत की सांस्कृतिक स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश वह भूमि है जहां कई ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर युवाओं के लिए एक नयी रोजगार पहल की घोषणा की और कहा कि यह युवाओं की क्षमताओं को नौकरी व व्यापार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद प्रधानमंत्री का पत्र मंच से पढ़ा, जिसमें मोदी ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत, विकास की दिशा, बेहतर हुए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के समारोह राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य के बाहर तथा विदेश में रहने वाले लोग भी विभिन्न तरीकों से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में लगभग 100 एकड़ भूमि का विकास किया जाएगा, जिससे कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं की क्षमता बढ़ेगी। उन्हें नौकरी व व्यापार के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। एक जिला, एक उत्पाद कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद की है, और अब एक जिला–एक व्यंजन कार्यक्रम जिले के विशिष्ट पारंपरिक खाद्य पदार्थों को वैश्विक पहचान दिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। एक जिला, एक व्यंजन (ओडीओसी) पहल के तहत, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मोटा अनाज आधारित उत्पाद भी शामिल होंगे और स्थानीय व्यंजनों की जियोग्राफिकल टैगिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग की जाएगी। इससे घरेलू और वैश्विक मांग बढ़ेगी, जिससे राज्य के पारंपरिक व्यंजनों के लिए निर्यात के अवसर खुलेंगे।

कहना न होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावना के अनुरूप उत्तर प्रदेश दिवस को कुछ इस तरह से मनाया गया, जिसमें प्रदेश के हर आम और खास को हर स्तर पर उत्तरप्रदेश की आत्मा के दर्शन हुए। इसी तारीख को वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यूपी दिवस मनाने के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मई 2017 को घोषणा की थी कि वह हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाएगी। तब से हर साल यूपी दिवस का आयोजन अलग–अलग थीम पर किया जा रहा है। विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा पर उत्तर प्रदेश दिवस –2026 व्यापक जनभागीदारी के साथ अत्यंत भव्य तरीके से मनाया गया। राज्य और जनपद स्तर पर

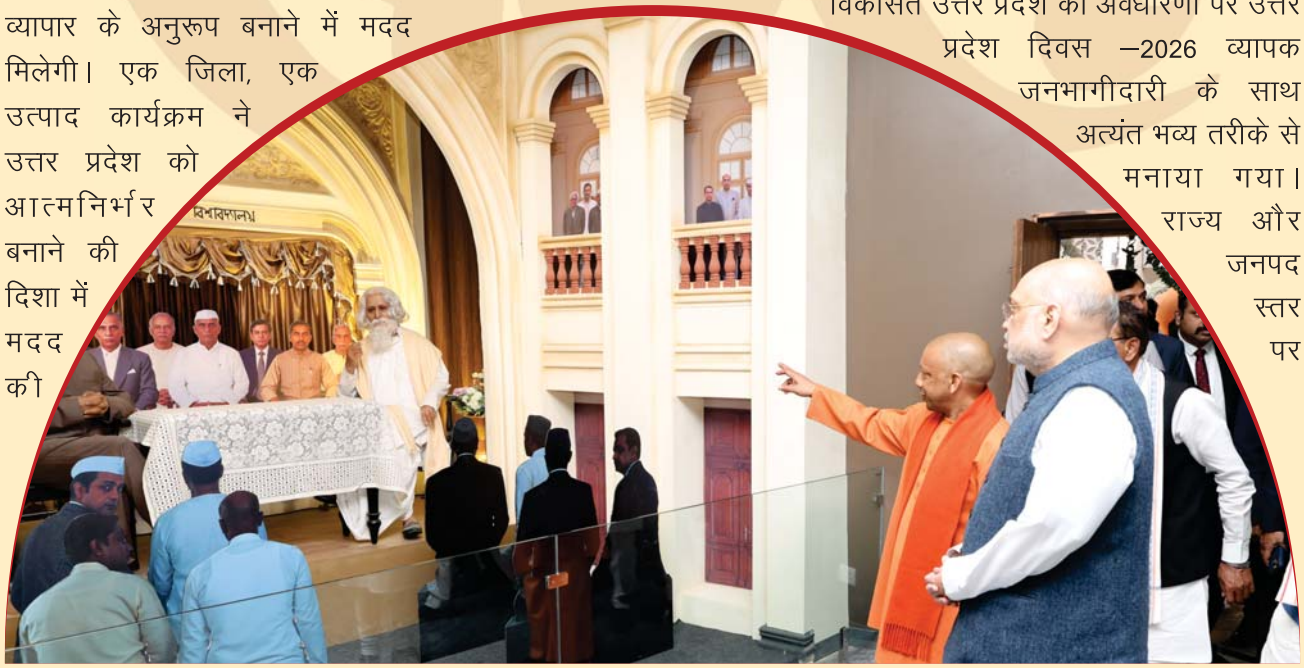

यूपी दिवस मनाया गया। आकर्षक प्रदर्शनियों और सम्मान समारोहों के बीच लोगों को उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत से रूबरू होने का मौका मिला। यूपी के स्थापना दिवस 24 जनवरी से गणतंत्र दिवस तक राज्यभर में कार्यक्रमों की धूम लोगों को रोमांचित करती रही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानें तो 1775 से 1833 तक यह क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश फोर्ट विलियम (बंगाल) के अधीन था। 1834 में इसे बंगाल से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया और 1836 में इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज पड़ा। 1902 में इसे 'नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध' और 1937 में 'यूनाइटेड प्रोविंसेज' नाम दिया गया। अंततः 24 जनवरी, 1950 को इसे 'उत्तर प्रदेश' के नाम से पहचाना गया। तब से आज तक भारत के इस सबसे बड़े प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही है।

विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया गया, जबकि जनपद स्तर पर भी इसदिन भव्य आयोजन किए गए। सभी जनपदों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से किया गया। जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा से जुड़े अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए गए। इससे लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी सहज और प्रभावी ढंग से पहुंच सकी। एक जनपद–एक उत्पाद योजना के तहत शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और उन उत्पादों को प्रमुखता से बेचा भी गया। जीआई टैग प्राप्त ओडीओपी उत्पादों को ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही एक जनपद–एक व्यंजन के उत्पादों का भी प्रदर्शन और विक्रय किया गया।

विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की अवधारणा पर राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया गया, जबकि जनपद स्तर पर भी इस दिन भव्य आयोजन किए गए। सभी जनपदों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य रूप से किया गया। जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा से जुड़े अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए गए। इससे लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी सहज और प्रभावी ढंग से पहुंच सकी। एक जनपद–एक उत्पाद योजना के तहत शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और उन उत्पादों को प्रमुखता से बेचा भी गया।

लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मिशन शक्ति, नवाचार और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियां लगाई गईं। इस अवसर पर युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्वों, पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, संस्कृति–कला जगत की हस्तियों, खेल, पंचायती राज, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि और श्रम विभाग से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। युवा कल्याण विभाग की ओर से इसी अवधि में युवाओं के लिए प्रेरक कार्यक्रम हुए। प्रतियोगिताएं हुईं और उन्हें पुरस्कार दिए गए। फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से विदेशों में भी उत्तर प्रदेश दिवस–2026 का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के लिए एमएसएमई और पर्यटन विभाग द्वारा सोवेनियर उपलब्ध कराए गए। यूपी दिवस से एक दिन पूर्व 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी जनपदों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित की गई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। संस्कृति उत्सव 2025–26 के तहत पहले ही 10 से 15 जनवरी तक ग्राम पंचायत, ब्लॉक और तहसील स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 17 से 19 जनवरी तक मंडलीय मुख्यालयों पर जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं, 22 जनवरी को लखनऊ में मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं, 23 जनवरी को

विजेताओं का पूर्वाभ्यास और 24 से 26 जनवरी तक विजेताओं की प्रस्तुतियां, सम्मान और पुरस्कार वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 12 से 23 जनवरी, 2026 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में साफ–सफाई सुनिश्चित की गई।

इसमें संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास न केवल गौरवशाली है बल्कि अत्यंत रोचक और ज्ञानबर्द्धक भी है। देश में अलग–अलग राजाओं के राज्य थे। मुगल काल में अकबर ने जब सत्ता संभाली तो कुछ वर्षों के लिए उसने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसने प्रयागराज का नाम बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया और 1583 में उसे अपनी राजधानी बना लिया। नवाबों के दौर में अवध के नवाब सआदत अली खां ने अयोध्या को अपना निवास बनाया और फैजाबाद नाम के एक नए शहर का गठन कर उसे अवध की राजधानी घोषित किया। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में राज्यों का पुनर्गठन किया। संयुक्त प्रांत आगरा–अवध करते हुए इलाहाबाद को फिर राजधानी बना दिया। वर्ष 1834 तक तो इलाहाबाद ही राजधानी रही, लेकिन 1834 में आगरा राजधानी बना दी गई। प्रांत का नाम भी बदलकर उत्तर–पश्चिम प्रांत कर दिया गया लेकिन, 1858 में तत्कालीन वायसराय लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को फिर राजधानी बना दिया। इसी के साथ 1877 में प्रांत का नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया। पर, स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान जब भारतवासियों के संघर्ष के सामने झुकते हुए अंग्रेजों ने सशर्त सरकार बनाने पर सहमति दी तो राज्य का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। वर्ष 1921 तक इलाहाबाद ही राजधानी रही लेकिन 1921 में लखनऊ को

राजधानी बना दिया गया। तब से आज तक लखनऊ ही तब के संयुक्त प्रांत और अब के उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गौरतलब है कि 24 जनवरी, 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ और बाद में पुनर्गठन कर उत्तर प्रदेश का मौजूदा स्वरूप तय किया गया। 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तरांखड बनाया गया। पहले इसका नाम उत्तरांचल फिर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की पांच सीटें भी उत्तराखंड में दी गईं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 85 की जगह लोकसभा की 80 ही सीटें रह गईं। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ था। 24 जनवरी से 26 जनवरी, 2025 तक चले इस तीन दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था।

उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के ई–पोर्टल की लॉन्चिंग की गई और 25 हजार युवा उद्यमियों को उनके उद्यम की स्थापना के लिए ऋण और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। साथ ही प्रदेश के छह लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस को राज्य की समृद्धि और गौरव का उत्सव करार दिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जीरो पावर्टी' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष जब हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएं, तब हर गरीब के पास सिर छिपाने के लिए छत हो, जमीन का पट्टा हो, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि हम जाति, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर हर गरीब और वंचित को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कसौटी पर सरकार बहुत हद तक खरी उतरी है और अपने दावे को शत–प्रतिशत पूर्ण करने का उसका प्रयास अद्यावधि जारी है और आगे भी जारी रहेगा, इसकी कल्पना तो की ही जा सकती है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य राज्य भी अपना स्थापना दिवस मनाने लगे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जिसके जन भवन में सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जिस तरह अपनी आध्यात्मिक विरासत को सहेज रहा है। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश का फूड बास्केट बन रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क के मामले में यह देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं और प्रयास से उत्तर प्रदेश 'उद्यमियों का प्रदेश' और देश के विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश दिवस मनाने में किसी को भी गौरव की अनुभूति होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अगर उत्तर प्रदेश को देश की धड़कन कहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश भी इस सच को जानता है और इसी हिसाब से प्रगति पथ पर आगे भी बढ़ रहा है जिससे वे विकसित भारत का इंजन बनने का गौरव अपने नाम कर सके। ◆

मो. : 7459998968

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

यूपी में सरपट दौड़ रहा विकास का पहिया

—यशोदा श्रीवास्तव

किसी भी देश या प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मायने रखती है। कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ मानव रक्षा ही नहीं है, यह प्रदेश में विकास के नए द्वार भी खोलती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन भी रोकती है, परिवारों में खुशहाली और समृद्धि का माहौल पैदा करती है।

उत्तर प्रदेश को जब हम 2017 के पहले देखते हैं तो बेहिचक कह सकते हैं कि यह वाकई एक बीमार प्रदेश था। उद्योग के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में रोजगार और खुशहाली के मामले में, सड़क और सिंचाई के मामले में भी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग चीनी था। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश खास था क्योंकि यहां चीनी मिलों की अधिकता थी इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा तक कहा जाता था और गोरखपुर को खाद का हब!

गोरखपुर का विख्यात खाद कारखाना बंद पड़ा था, वर्षों तक इसका कोई पुरसाहाल नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन से ही वे बंद पड़े इस खाद कारखाना के उद्धार की जुगत में जुट गए। वे जानते थे कि पूर्वांचल की उपजाऊ मिट्टी को खाद की कितनी जरूरत है। अंततः खाद कारखाने का उद्धार हुआ और इसी के साथ पूर्वांचल के किसानों की दुश्वारियां भी दूर हुईं। यह तो बतौर मुख्यमंत्री उनके पहले के कार्यकाल की बानगी है। लेकिन वे यहीं चुप नहीं बैठे। वे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जाल बिछाने के साथ यहां देश और विदेश से भारी निवेश की राह कैसे आसान हो, उद्योगपतियों और निवेशकों का ध्यान यूपी की ओर कैसे आकृष्ट हो, इसकी रणनीति बनाने में भी जुट गए।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के कारणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और पाया कि यहां बाहरी निवेश और उद्योगों के पिछड़ने की बड़ी वजह कानून व्यवस्था और अनावश्यक

राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर जोर दिया जिसकी अनुभूति आज हर यूपीवासी कर रहा है। कामकाजी महिलाएं कर रहीं हैं,और माफियाओं के डर से कांप रहे तमाम सारे लोग भी कर रहे हैं। संगठित अपराध और माफिया जनित अपराध के मामले में निसंदेह यूपी आज जीरो टॉलरेंस की श्रेणी में है।

उत्तर प्रदेश के बीमार प्रदेश के कारणों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और पाया कि यहां बाहरी निवेश और उद्योगों के पिछड़ेपन की बड़ी वजह कानून व्यवस्था और अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले कानून व्यवस्था पर जोर दिया जिसकी अनुभूति आज हर यूपी वासी कर रहा है। कामकाजी महिलाएं कर रही हैं, और माफियाओं के डर से कांप रहे तमाम सारे लोग भी कर रहे हैं। संगठित अपराध और माफिया जनित अपराध के मामले में निःसंदेह यूपी आज जीरो टॉलरेंस की श्रेणी में है।

पश्चिम बंगाल के सिंगूर की घटना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताती है कि राजनीतिक आंदोलन भी बड़े उद्योग का बेड़ा गर्क कर देते हैं और बाहरी निवेश के दरवाजे बंद कर देते हैं। रतन टाटा ने 2006 में नैनो नाम की छोटी कार के उत्पादन की आधारशिला सिंगूर में रखी थी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस परियोजना के खिलाफ ऐसा गदर काटा कि 2008 में टाटा को अपनी इस परियोजना को वहां से हटाने को मजबूर होना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के कारण कर्मचारियों और विक्रेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता और चुनौती का माहौल पैदा हो गया था। अंततः टाटा को अपनी इस परियोजना को साणंद (गुजरात) स्थानांतरित करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सूझ बूझ और कुशल रणनीति से माहौल काफी बदला है। खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। निवेशकों की सरकारी सुविधाओं के लिए भी काफी लचीलापन रवैया अख्तियार किया गया।यहां बाहरी निवेश और उद्योग स्थापना में फिलहाल कानून व्यवस्था और राजनीतिक आंदोलन की संभावना दूर–दूर तक नहीं है। इसका असर साफ–साफ दिख भी रहा है। विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास की बढ़ रही रफ्तार यूपी में साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल की गवाही खुद ब खुद दे रहे हैं।

यूपी में विदेशी निवेश के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के बाद 2025 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3,303 करोड़ से बढ़कर 16,316 करोड़ हुआ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रमुख निवेश विनिर्माण (62.25 प्रतिशत), सेवा क्षेत्र में (28.09 प्रतिशत) जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनियादी ढांचे,और फार्मास्युटिकल में आए हैं जिसमें वीवो,टाटा,अडानी, पेप्सी को और आइकिया जैसी कंपनियां शामिल हैं।

पिछले दस वर्षों में मुख्य निवेश की बात करें तो यह 2017 से पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच यूपी में करीब 14 हजार करोड़ का विदेशी निवेश आया है। सबसे अधिक 62.25 प्रतिशत निवेश निर्माण क्षेत्र में आया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा विनिर्माण मुख्य है। इसके बाद सेवा क्षेत्र है जिसमें 28.09 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां 196 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां कार्यरत हैं। रियल स्टेट, फार्मास्युटिकल और ट्रेडिंग में भी विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। 2025–26 की संभावनाओं पर बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में ही 5,963 करोड़ विदेशी निवेश हासिल हुआ है। इस तरह देखें तो उत्तर प्रदेश एफडीआई के लिए देश का ग्यारहवां आकर्षक राज्य बन गया है। यूपी और भी कई मामलों में तेजी से विकसित होता राज्य बन रहा है। यह सब अनायास या भाग्य भरोसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक संत मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति और पवित्र संकल्प है।

जिस तेजी से यूपी में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों का जाल बिछ रहा है, उसका लाभ निःसंदेह यूपी के होनहार युवाओं को मिलेगा जो अभी यूपी के बाहर या दूसरे देशों में अपने भविष्य के सपने देखने को मजबूर थे। उसी तरह निर्माण क्षेत्र में युवा अपने कौशल विकास के बल पर आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं को यूपी के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराने का अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभा जा रहे हैं। निश्चित ही इससे यूपी के युवाओं के पलायन पर भी विराम लगेगा। ◆

मो. : 9918955583

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

विकसित उत्तर प्रदेश का बजट

–प्रमोद शुक्ला

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। विगत 11 फरवरी को प्रस्तुत इस बजट के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पनाओं को समर्पित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने विगत नौ वर्षों के दौरान अपना परसेप्सन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य ने पॉलिसी पैरालिसिस से उबरकर अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यह बजट इन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। विगत नौ वर्षों में प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है। आज नौ लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम तथा तकनीकी क्षेत्र में निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश' के लिए समर्पित यह बजट नववर्ष के नवनिर्माण की नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029–30 में एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए है। परिसम्पत्तियों के नवनिर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार सृजन

होता है। विगत नौ वर्षों में वर्तमान सरकार का दसवां बजट है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री को दसवां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 30 प्रतिशत से अधिक थी, उसे हम 27 प्रतिशत लाने में सफल हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता उसकी जीएसडीपी की 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश वेलफेयर व इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रत्येक सेक्टर में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत से कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर 17 से 19 प्रतिशत तक थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता था कि अलग–अलग विभाग अलग–अलग समय में अलग–अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। वर्तमान सरकार ने तय किया कि प्रदेश में 'स्टेट डाटा अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा। यह अथॉरिटी रियल टाइम डाटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी।

उन्होंने कहा कि इस बजट में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई डाटा लैब्स तथा साइबर फ्रॉड को रोकने हेतु बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में प्रदेश की रैंकिंग 13–14 पर थी। वर्तमान सरकार ने पहले तीन वर्षों में इसे दूसरे नम्बर पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश ने चीफ अचीवर्स स्टेट के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अब जन–विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेशकों के लिए 'सिंगल विंडो' के माध्यम से लाइसेंसिंग, पंजीकरण आदि की कार्यवाही को अधिक सहज व सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए गये हैं। प्रदेश में डिजिटल इण्टरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में बजट में प्रावधान किए गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने विगत नौ वर्षों के दौरान अपना परसेप्सन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य ने पॉलिसी पैरालिसिस से उबरकर अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यह बजट इन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। विगत नौ वर्षों में प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है। आज नौ लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम तथा तकनीकी क्षेत्र में निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश' के लिए समर्पित यह बजट नववर्ष के नवनिर्माण की नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई की क्षमता में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। प्रदेश में 40 लाख ट्यूबवेल में से विद्युत से संचालित 16 लाख ट्यूबवेल के लिए निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गई। डीजल से संचालित शेष 23 लाख ट्यूबवेल को फेजवाइज सोलर पावर से जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा इस बजट में हुई है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला एवं सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष–2026 के उपलक्ष्य में बजट में एफपीओ को अतिरिक्त सुविधा से फैसिलिटेट करने के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में गन्ना के साथ तिलहनी व

दलहनी अन्तःफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गये हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना' के अंतर्गत 85 प्रतिशत तक प्रीमियम राज्य सरकार देगी। लैंडलॉक्ड स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति देश में बहुत बेहतर है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 'स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मंडी' और 'फिश प्रोसेसिंग सेंटर' के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में आगरा–लखनऊ– हरदोई–फर्रुखाबाद की गंगा एक्सप्रेस–वे से कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस–वे का विस्तार प्रयागराज से मीरजापुर, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र के शक्तिनगर तक तथा मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस–वे को गाजीपुर से चन्दौली, सोनभद्र के शक्तिनगर तक ले जाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 'वन डिस्ट्रिक्ट–वन कुजीन योजना' के अंतर्गत स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्राडिंग के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। पुराने कम्बल एवं ऊन कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनपद में हब एंड स्पोक मॉडल पर स्किल डेवलपमेंट के बड़े केंद्र विकसित करने के कार्य को सरकार आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सभी जनपदों में सरदार वल्लभभाई पटेल एंप्लॉयमेंट जों 50 एकड़ से लेकर 100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए 'स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना' के अंतर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई मॉडल दिए हैं, जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प, अटल आवासीय विद्यालय प्रमुख हैं। अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में दो–दो सीएम कम्पोजिट विद्यालय की स्थापना हेतु बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करें, इसके लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए 'वन कमिश्नरी–वन स्पोर्ट्स कॉलेज' अर्थात 18 कमिश्नरी हेड क्वार्टर्स पर एक–एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024–25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों, ईको–टूरिज्म, हेरिटेज–टूरिज्म एवं एडवेन्चर से जुड़े अन्य पर्यटन केंद्रों पर यात्रा की। एक नई व्यवस्था करते हुए एक लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने की दिशा में पर्यटन पॉलिसी के अंतर्गत पीपीपी मोड पर कार्य किया जाएगा। 50 हजार नये होम–स्टे के लिए भी कार्य किया जाएगा। महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए लगने वाले 10 हजार रुपये के लाइसेंस शुल्क को माफ करने की भी बजट में व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत नौ वर्षों में नई प्रगति की है। प्रदेश में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 17 से कम सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज, दो एम्स तथा अनेक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा कि एसजीपीजीआई देश का पहला सेंटर होगा, जहां टर्शियरी के बाद क्वार्टनरी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए पहले चरण में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ–साथ यदि कोई घटना–दुर्घटना या कोई आपदा आती है, तो उन परिस्थितियों में ट्रॉमा सेंटर को सशक्त बनाने तथा नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में मेडिकल तथा हेल्थ सेक्टर में मेड–टेक की स्थापना होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा में बेटियों विशेषकर मेरिटोरियस छात्राओं को स्कूटी देने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने हेतु स्मार्टफोन/टैबलेट की अतिरिक्त व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में अथवा ट्रेनिंग ले रही किसी दिव्यांग छात्रा के लिए ई–ट्राई साइकिल अर्थात मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में डीडीआरसी की स्थापना हो, जहां दिव्यांगजन हेतु नजदीकी सेंटर में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण किया जा सके, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तीन से सात वर्ष के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु डे–केयर सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर जनपदों में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। नौ जनपदों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में तीन से सात वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। ◆

मो. : 9451957606
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राष्ट्र-निर्माण की पाठशाला : राष्ट्र प्रेरणा स्थल

—शिवानी कटारा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल मात्र पत्थरों और प्रतिमाओं का समूह नहीं, बल्कि वह जीवंत चेतना है जहाँ विचार संस्कार बनते हैं और संस्कार राष्ट्र–निर्माण की दिशा लेते हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और वैचारिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में अंकित हो गया जो स्मृति को साधना में रूपांतरित करता है और विरासत को भविष्य की चेतना से जोड़ देता है। यह स्थल अपने आप में सुशासन, दृढ़ संकल्प और सतत विकास की जीवंत मिसाल है। युवा पीढ़ी के लिए यह स्थल संदेश देता है कि राष्ट्र–सेवा केवल स्मरण का विषय नहीं, बल्कि निरंतर साधना है–जहाँ विचार, कर्म और चरित्र एक–दूसरे से जुड़ते हैं।

पृष्ठभूमि और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि

लखनऊ के बाह्य क्षेत्र में हरदोई रोड पर, गोमती नदी के सान्निध्य में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लगभग ₹230 करोड़ की लागत से लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत कुंज योजना के अंतर्गत किया गया। वर्ष 2022 में आरंभ हुई यह परियोजना 65 एकड़ में फैले परिसर के रूप में आकार लेती हुई एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर की संकल्पना को साकार करती है– जिसका उद्देश्य नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और जन–प्रेरणा को संस्थागत रूप देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे केवल निर्माण–परियोजना नहीं, बल्कि युवाओं के चरित्र–निर्माण की प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया है।

परिसर के केंद्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की

65 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं–प्रत्येक प्रतिमा का वजन लगभग 42 टन है। प्रतिमाओं के चबूतरों के चारों ओर निर्मित जलकुंड शांति, संतुलन और निरंतरता का प्रतीक है। यह स्थापत्य युवाओं को बोध कराता है कि विचारों की ऊँचाई तभी सार्थक है जब वह समाज के हर स्तर तक शीतलता और प्रकाश पहुँचा सके।

उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा– "राष्ट्र प्रेरणा स्थल आत्मसम्मान, एकता और सेवा की उस भावना का सजीव रूप है जिसने भारत को दिशा दी। यहाँ स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाएँ हमें बताती हैं कि राष्ट्र–निर्माण के लिए हर कदम और हर प्रयास समर्पित होना चाहिए।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह रेखांकित किया कि इन महान और यशस्वी नेताओं ने स्वतंत्र भारत की पहचान को स्वर दिया, आत्मसम्मान को आधार प्रदान किया और राष्ट्र के दीर्घकालिक उद्देश्य को स्पष्ट दिशा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे "नई राष्ट्रीय दृष्टि" का मूर्त रूप बताते हुए कहा कि यह स्थल एक भारत–श्रेष्ठ भारत और अंत्योदय की भावना को ठोस आकार देता है। यह समूचा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन–केन्द्रित विकास नीति की ठोस उपलब्धि है।

लखनऊ के बाह्य क्षेत्र में हरदोई रोड पर, गोमती नदी के सान्निध्य में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लगभग ₹230 करोड़ की लागत से लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत कुंज योजना के अंतर्गत किया गया। वर्ष 2022 में आरंभ हुई यह परियोजना 65 एकड़ में फैले परिसर के रूप में आकार लेती हुई एक स्थायी राष्ट्रीय धरोहर की संकल्पना को साकार करती है– जिसका उद्देश्य नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और जन–प्रेरणा को संस्थागत रूप देना है।

संरचना और जन–सुविधाएं

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का नियोजन विशालता और समावेशन–दोनों का संतुलन है। परिसर में करीब दो लाख लोगों की क्षमता वाला रैली ग्राउंड, 3,000 सीटों का एम्फीथिएटर, ध्यान कक्ष, योगा एवं विपश्यना केंद्र, म्यूजिक ब्लॉक, कैफेटेरिया, हेलीपैड और अन्य नागरिक सुविधाएं सम्मिलित हैं। यह केवल स्मरण–स्थल नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद और सांस्कृतिक सहभागिता का केंद्र है जहाँ विचारों पर विमर्श, कला–प्रस्तुति और युवा संवाद संभव हैं।

वास्तुकला में कमल का रूपक शुद्धता, उत्थान और राष्ट्रीय चेतना को उभारता है। खुले आकाश और हरित क्षेत्र परिसर को शांति देते हैं, ताकि आगंतुक

स्मरण के साथ आत्मचिंतन भी कर सकें। यह संरचना युवाओं को मौन किन्तु प्रभावशाली संदेश देती है कि राष्ट्र–प्रेरणा केवल इतिहास के पन्ने पलटने से नहीं उपजती, बल्कि विचारों की ऊँचाई, संकल्प की गहराई, कर्म की निरंतरता और चरित्र की दृढ़ता से संभव होती है। वह अनुभव की कोख से जन्म लेती है– जहाँ शरीर, मन और बुद्धि एक साथ सक्रिय हों।

उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा– "राष्ट्र प्रेरणा स्थल आत्मसम्मान, एकता और सेवा की उस भावना का सजीव रूप है जिसने भारत को दिशा दी। यहाँ स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाएँ हमें बताती हैं कि राष्ट्र–निर्माण के लिए हर कदम और हर प्रयास समर्पित होना चाहिए।"

आधुनिक संग्रहालय : विचारों की जीवंत पाठशाला

परिसर का हृदय है अत्याधुनिक म्यूजियम, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला है और दो मंजिलों, पाँच गैलरियों तथा पाँच कोर्टयार्ड्स में विभक्त है। उन्नत डिजिटल और इमर्सिव तकनीक– ऑडियो–विजुअल, इंटरैक्टिव पैनल, सिलिकॉन मूर्तियाँ–इतिहास को बोझ नहीं, प्रेरणा बनाकर प्रस्तुत करती हैं। पहली गैलरी (ओरिएंटेशन रूम) में सरल भाषा और प्रभावी दृश्यों के माध्यम से तीनों राष्ट्र नायकों के जीवन–पड़ावों का समग्र परिचय मिलता है–ताकि आगंतुक आगे की गैलरियों को सही संदर्भ में समझ सकें। दूसरी गैलरी, भारतीय जनसंघ के गठन और विकास को समर्पित है–फोटो, दस्तावेज और अख़बारों की कतरनें दिखाती हैं कि कैसे एक वैचारिक आंदोलन संगठित राजनीतिक धारा बना। तीसरी गैलरी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्ष, सिद्धांत और बलिदान को सामने लाती

है—कश्मीर से राष्ट्रीय एकता तक उनके विचारों को दुर्लभ तस्वीरों और दृश्यों से समझाया गया है, उस जेल का दृश्य—प्रदर्शन भी है, जहाँ वे बंद रहे। चौथी गैलरी, पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को जीवन—दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है—दीवारों पर उकेरे उद्धरण बताते हैं कि राजनीति का उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय है। पाँचवीं गैलरी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है—उनकी कविताएँ, भाषणों की झलकियाँ और राजनीतिक जीवन के निर्णायक क्षण युवाओं को लोकतांत्रिक मर्यादा, संवाद और राष्ट्रहित की शिक्षा देते हैं।

म्यूजियम के कोर्टयार्ड्स प्रतीकात्मक गहराई से जोड़ते हैं—भारत माता कोर्टयार्ड में 10 फीट ऊँची प्रतिमा और दीवार पर अंकित वंदे मातरम् राष्ट्रभक्ति को सशक्त करता है। अन्य कोर्टयार्ड्स में दीपक (विचारों की रोशनी) और सुदर्शन चक्र (न्याय और धर्म—रक्षा) के प्रतीक हैं। दूसरे फ्लोर पर राष्ट्रनायकों द्वारा प्रयुक्त तख्त, प्रिंटिंग मशीन, मेज—कुर्सी और छड़ी प्रदर्शित हैं—वह प्रिंटिंग मशीन भी, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों ने पर्चे—अख़बार छापे। 12 इंटरप्रिटेशन वॉल्स म्यूरल और रिलीफ आर्ट के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और महान विभूतियों की कथा कहती हैं—कला और इतिहास का ऐसा संगम, जो हर उम्र को जोड़ता है। आधिकारिक आयोजनों हेतु वीवीआईपी ग्रीन रूम यह बताता है कि यह स्थल स्मृति के साथ सक्रिय सार्वजनिक संवाद का केंद्र भी बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि "यह अत्याधुनिक संग्रहालय निःस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन की भावना को सजीव करता है, आने वाली पीढ़ियों को हमारे नेताओं के आदर्श अपनाने की प्रेरणा देता रहेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि जिस भूमि पर वर्षों कचरा जमा था, उसे साफ कर यह प्रेरक परिसर खड़ा किया गया, यह परिवर्तन की राजनीति का प्रमाण है। साथ ही सोशल मीडिया पर दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने अटल जी को स्मरण करते हुए कहा कि "अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और राष्ट्र—निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता थे। वे प्रखर वक्ता ही नहीं, संवेदनशील कवि भी थे, उनका नेतृत्व देश के सर्वांगीण विकास का पथ दिखाता रहेगा।"

निष्कर्षतः, राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी और कालजयी उपलब्धि है जो युवाओं को केवल इतिहास से परिचित नहीं कराता, बल्कि उसे जीने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह स्थल भारतीय राष्ट्र चेतना के इतिहास को सजीव बनाते हुए शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैचारिक पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर उभर रहा है, जहाँ अध्ययन, अनुभूति और आत्मचिंतन एक साथ संभव हैं। ◆

मो. 9205269749

(लेखिका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं)

पीठासीन अधिकारियों का महासंगम

—राधिका

86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बेहद मायने रखता है और जब यह आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सशक्त विधायिका–समृद्ध राष्ट्र की अवधारणा के तहत आयोजित इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम में देश के 24 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया और अपनी सम्मति से विचार मंथन को एक नई ऊंचाई दी। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर तो विमर्श हुआ ही, 'उत्तर प्रदेश कैसे बन रहा है सर्वोत्तम प्रदेश' विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। फिल्म में प्रदेश के तीर्थ स्थल, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, रानी लक्ष्मीबाई, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काशी की परंपराएं तथा बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर और पंडित बिरजू महाराज जैसी महान विभूतियों का चित्रण इस सम्मेलन को यादगार बना गया।

देशभर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों ने यह बात प्रमुखता से कही कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जहां देश की सभी विधानसभाओं के पेपरलेस होने और उनकी कार्यवाही के सजीव प्रसारण की बात कही,वहीं जनता के बीच सदन की कार्यवाही की जानकारी निर्बाध रूप से पहुंचने पर प्रसन्नता भी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने बेहद पते की बात कही कि जनता का विश्वास जीतना और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना विधायिकाओं का सबसे बड़ा दायित्व है। सदस्य भले ही अलग–अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से जुड़े हों, लेकिन जनता केवल इतना ही चाहती है कि उनके मुद्दे पूरी मजबूती से सदन में उठाए जाएं। उन्होंने बहुत सुस्पष्ट शब्दों में कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस पर हमें गर्व है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 साल में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और देश भर में प्रदेश को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। नेता वही बन सकता है जो समाज के हर वर्ग को समझता हो। विधानसभा में पीएचडी उपाधि धारक, सेवानिवृत्त आईएएस–आईपीएस अधिकारी, जमीनी कार्यकर्ता और सफाईकर्मी तक विधायक बनकर आते हैं और समाज को दिशा देते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है।

इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि संवाद और विचार–विमर्श लोकतंत्र के मूल आधार हैं, जो पारदर्शिता बढ़ाने और विविध मतों के सम्मान में सहायक होते हैं।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने विधानसभाओं के संचालन के लिए स्पष्ट और सुनिश्चित समय–सीमा तय किए जाने की जरूरत पर तो बल दिया ही,यह भी रेखांकित किया कि अल्प अवधि के सत्रों में कई बार विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता, जिससे जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा बाधित होती है। राज्यपाल ने कहा कि यदि विधानसभाएं अल्प अवधि के लिए संचालित होती हैं, तो समयाभाव में जनप्रतिनिधियों की आवाज पूरी तरह सदन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सदनों की कार्यवाही को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए उनकी अवधि का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में लोकसभा अध्यक्ष के सुझाव को बेहद अहम करार दिया और उम्मीद जताई कि इस पर गंभीरता से विचार होगा और सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह सम्मेलन भारतीय संसदीय परंपराओं की सुदृढ़ता, मर्यादा और निरंतरता का जीवंत प्रतीक है। लखनऊ की तहजीब, संवाद और समन्वय की परंपरा इस

आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान करती है। पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र की आत्मा के संरक्षक हैं। उनकी निष्पक्षता, विवेक और मर्यादित आचरण ही सदनों को जनआकांक्षाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति का मंच बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक विरासत है। यह प्रदेश वैदिक संस्कृति, दर्शन और लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र रहा है। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसी पावन धरती ने भारत की आत्मा और उसके मूल्यों को दिशा दी है। विधानमंडल जनआकांक्षाओं को स्वर देने का पवित्र मंच है और सदन की सार्थकता केवल बहसों की संख्या से नहीं, बल्कि लोककल्याण की भावना, तथ्यपरक और समाधानोन्मुख संवाद से तय होती है। संवाद जब समाधान में परिवर्तित होता है, तभी संसदीय लोकतंत्र सशक्त और विश्वासयोग्य बनता है। राज्यपाल ने सदन की कार्यवाहियों में व्यवधान को एक गंभीर चुनौती करार दिया। इससे जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाधित होती है और लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित होता है। विचारों की भिन्नता लोकतंत्र की शक्ति है। असहमति को लोकतांत्रिक सौंदर्य के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 साल में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है और देश भर में प्रदेश को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। नेता वही बन सकता है जो समाज के हर वर्ग को समझता हो। विधानसभा में पीएचडी उपाधि धारक, सेवानिवृत्त आईएएस–आईपीएस अधिकारी, जमीनी कार्यकर्ता और सफाईकर्मी तक विधायक बनकर आते हैं और समाज को दिशा देते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग से ही लोकतंत्र आगे बढ़ता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विधायिका लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। संविधान की संरक्षक है। यह न केवल देश में विधायी कार्यों के लिए रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि यह समग्र विकास की कार्ययोजना का मंच भी होती है। संविधान के तीन शब्द न्याय, समता और बंधुता लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय प्राप्ति के लिए कानून विधायिका के मंच पर तैयार होता है। समतामूलक समाज की स्थापना में सरकार की योजनाएं सहायक हो सकें, उसकी कार्ययोजना का स्थल भी विधायिका का मंच बनता है। विधायिका बंधुता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां सहमति व असहमति के बीच संवाद समन्वय का सेतु बनता है।

उन्होंने कहा कि सतीश महाना ने 2022 में विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व संभाला तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं, लेकिन सवा घंटे के प्रश्नकाल में केवल दो–तीन सदस्य ही बोल पाते हैं। क्या हम भी इसे संसद की तर्ज पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर उन्होंने तत्काल नियमावली में परिवर्तन किया। अब सवा घंटे में 20 तारांकित प्रश्न और हर प्रश्न के साथ दो–तीन अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले मंत्री पूरी तैयारी के साथ आते हैं। सदन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता दिखती है। संसद हमारे लिए प्रेरणास्रोत है। हमारे पास सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद है। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो संसद ही उसका आधार बनती है, उसके प्रति श्रद्धा हर भारतवासी का दायित्व है। भारत लोकतंत्र की जननी है। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को गांवों ने साकार किया। देश में रूप–रंग, खान–पान, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा भारत एक भाव–एक भंगिमा के साथ बोलता और सोचता है। उसकी आस्था एक होती है। संसद उस आस्था को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। संसद को आदर्श के रूप में बढ़ाएंगे तो विधायिका और सशक्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन में पारित हुए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अभिनंदनीय बताते हुए कहा कि विजन 2047– विकसित भारत की परिकल्पना को साकार

करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर सत्तापक्ष व विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के सहभागी बने। चर्चा का शुभारंभ करने के बाद मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर अन्य प्रशासकीय कार्यों व बैठकों के लिए जाना पड़ा। रात 11 बजे मैं फिर सदन में आया तो भी यहां बोलने की होड़ दिखी। बहुत अच्छे सुझाव आए। हर व्यक्ति के अनुभव का लाभ अत्यंत प्रभावी होता है। विधानसभा–परिषद में लोगों ने विकास के बारे में मुद्दों को रखा और विकसित भारत के लिए अपनी जिम्मेदारी का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल भारत सरकार, प्रधानमंत्री का ही कार्य नहीं है, हम भी कैसे इस अभियान के सारथी–सिपाही बन सकते हैं, इस पर भी गहन आत्ममंथन हुआ। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए, प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सार्थक गति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में सदन की कार्यवाही अत्यंत सुगमता से चलती है। वर्ष में कम से कम 30 बैठकों का प्रस्ताव पारित किया जाना संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के लिए भी प्रेरणा है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विकास की धुरी बनते हैं। तकनीक के इस युग में हम खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सरकार के सामने यह बात आई कि ई–विधान होना है तो हमने कहा कि तत्काल इसे लागू कीजिए। आज यूपी की विधानसभा, विधान परिषद, कैबिनेट और बजट भी पेपरलेस हैं। जनप्रतिनिधि भी तकनीक से अपडेट हों, उनके उचित प्रशिक्षण समेत सभी प्रस्ताव बेहद अहम हैं। यूपी विधानसभा ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा–परिचर्चा चलाती है। स्थायी विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) पर भी यहां लगातार 37–38 घंटे चर्चा हुई। उसके लक्ष्य निर्धारित हुए। मंत्रिमंडल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर कमेटी गठित हुई, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों को भी हमने विधानसभा–परिषद में अनवरत चर्चा का विषय बनाया। हम विधायकों से कहते हैं कि यह चर्चा सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे ब्लॉक, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के स्तर तक विस्तारित करिए। हमने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से सुझाव लिए। हमारी विधानसभा और विधान परिषद में लगभग 500 जनप्रतिनिधि हैं। यूपी के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों समेत समाज के अन्य तबकों से जुड़े 500 लोगों की कार्यशाला की गई। उन्हें सेक्टर दिए, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए। सबसे कहा गया कि हर किसी को तीन–तीन संस्थाओं में जाकर युवाओं, किसानों, महिला स्वयंसेवी समूहों समेत विभिन्न तबकों को इस मुद्दे से जोड़कर चर्चा करनी है। विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश के लिए पोर्टल पर 98 लाख लोगों के सुझाव आए। एआई टूल के माध्यम से आईआईटी

कानपुर के साथ मिलकर हम उसे फाइनल रूप दे रहे हैं। अलग–अलग सेक्टर में आए सुझावों को विजन डाक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे। उस विजन डॉक्यूमेंट को लांच करेंगे। इससे हमारी कार्ययोजना के बेहतरीन परिणाम भी आएंगे। पीठ और सरकार का अप्रोच प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता। पीठ ने विपक्ष को अधिक मौका दे दिया तो सरकार रिएक्टिव नहीं होती। पीठ पक्ष–विपक्ष में संतुलन बनाती है। ऐसे सम्मेलन सीखने और सिखाने का मंच होते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि तीन दिन के इस सम्मेलन में देश के 24 राज्यों से कुल 36 सदस्य

शामिल हुए, जिनके साथ तीन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पहला विषय था पारदर्शी, कुशल और जनकेन्द्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग दूसरा कार्यकुशलता बढ़ाने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए विधायी संस्थाओं में सदस्यों में क्षमता निर्माण और तीसरा सबसे आवश्यक, जनता के प्रति सदस्यों की जवाबदेही। इन तीनों विषयों पर चर्चा के बाद 6 संकल्प लिए गए जिसमें सभी राज्यों की विधानसभाएं 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति करें और इसके लिए सभी विधानमंडलों में अपने राज्य के साथ–साथ देश के विकास पर चर्चा हो, यह पहला संकल्प था। दूसरा संकल्प था राज्य के विधानमंडलों में न्यूनतम 30 दिनों की बैठकें हों, ताकि हम रचनात्मक व प्रभावी रूप से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बना सकें। तृतीय संकल्प के तहत भारत के विधायी निकायों में बेहतर कार्य संचालन , इसके लिए प्रौद्योगिकी व एआई के उपयोग पर जोर दिया गया ताकि जनता व जन प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क स्थापित हो। साथ ही सबकी सार्थक रूप से सहभागिता सुनिश्चित हो। टेक्नोलॉजी के वर्तमान और आने वाले भविष्य को देखते हुए इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन, एआई के प्रयोग में पूरी सावधानी, जवाबदेही, विश्वसनीयता व नैतिकता भी होनी चाहिए। चौथा संकल्प था कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसेः पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा आदि में बेहतर संवाद हो, इसके लिए आदर्श नेतृत्व स्थापित हो। पांचवां संकल्प था कि विधानमंडलों के अंदर प्रभावी, सार्थक, तथ्यपूर्ण, ज्ञानपूर्वक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए विधायकों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग हो। सभी विधानमंडलों में रिसर्च विंग हों, पुरानी बहसें डिजिटलाइज्ड की जाएं और लाइब्रेरी डिजिटल हों, जबकि छठा संकल्प यह था कि विधायी निकायों के कार्य संचालन का वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर मूल्यांकन और तुलनात्मक आकलन करने के लिए एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाया जाए। गठित की गई कमेटी मानक तय करेगी, जिसके आधार पर विधायी निकायों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सम्मेलन के दौरान यह चर्चा भी हुई कि सभी पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष, निर्विवाद हों और सबके साथ संतुलन बनाकर आगे

बढ़ें। 2015 में भी जब उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन हुआ था, तब यहां संकल्प लिया गया था कि प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हो, पेपरलेस विधानसभाएं हों। खुशी की बात है कि आज देश की सभी विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं, सभी राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही लाइव प्रसारित होती हैं, सभी जगह रिसर्च विंग हैं। कई विधानसभाएं अपनी पुरानी डीबेट डिजिटलाइज्ड कर चुकी हैं और कुछ अभी कर रही हैं। इन कार्यों में लोकसभा की ओर से भी सहयोग दिया जा रहा है। जल्द ही सभी विधानसभाएं एक साथ डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म पर होंगी।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन के दौरान हुई सार्थक चर्चाओं पर गहरी संतुष्टि व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि देश भर के पीठासीन अधिकारियों के बीच विचारों के सामूहिक आदान–प्रदान ने चर्चा को काफी समृद्ध किया है। हरिवंश ने उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली आर्थिक प्रगति का जिक्र किया, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बजट के आकार में विस्तार, निर्यात में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विकास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा कभी समस्याग्रस्त राज्य के रूप में वर्णित उत्तर प्रदेश अब एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिसने पर्याप्त राजस्व वाले राज्य का दर्जा हासिल किया है और सुधारवादी शासन के लिए मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आज के बदलते भू–राजनीतिक परिवेश में राष्ट्रीय प्रगति के लिए आर्थिक शक्ति, रणनीतिक क्षमता और तकनीकी उन्नति अपरिहार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2014 से इस दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश एक नई पहचान बना रहा है। राज्य के विजन डॉक्यूमेंट–2047 का जिक्र करते हुए हरिवंश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में 27 घंटे से अधिक समय तक चली व्यापक चर्चा की सराहना की और इसे सहभागी शासन और आम सहमति बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य स्पष्ट और दूरदर्शी विकास रोडमैप तैयार करें और उत्तर प्रदेश इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2017 से 2025 के बीच, उत्तर प्रदेश में सुनियोजित और लक्षित क्रियाकलापों के माध्यम से लगभग छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का जिक्र किया जिसके तहत उत्तर प्रदेश को 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, अगले पांच वर्षों में विकास दर को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना और 2047 तक छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना तथा राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य की हिस्सेदारी को 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करना शामिल है।

विधानमंडलों और सरकारों की साझा जिम्मेदारी पर जोर देते हुए, हरिवंश ने कहा कि सभी हितधारकों का साझा उद्देश्य जागरूक विचार–विमर्श, सुदृढ़ नीति निर्माण और दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी और पारंपरिक विधायी मूल्यों के सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा डिजिटल उपकरणों को अपनाना, प्रक्रिया नियमों में सुधार करना, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज जैसी क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करना और साथ ही अनुवाद की सुविधा प्रदान करना तथा अध्यक्ष का सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना, सहभागिता और समावेशिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सहायक रहा है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश भर में विधायी संस्थानों को मजबूती मिलेगी और भारत की लोकतांत्रिक नींव को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। कुल मिलाकर यह सम्मेलन अपने आप में काफी प्रेरणादायक होता है। अगर इस पर अमल होता है, तो यह विधायिका के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। ◆

मो. : 6387005157

(लेखिका आईटी एक्सपर्ट हैं)

जेवर एयरपोर्ट : विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान

—डॉ. सौरभ मालवीय

उत्तर प्रदेश और भारत के उड्डयन क्षितिज पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च 2026 को गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया। यह अवसर केवल एक विश्वस्तरीय हवाई अड्डे के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि "विकसित उत्तर प्रदेश" और "विकसित भारत" के व्यापक दृष्टिकोण को गति देने वाला एक निर्णायक कदम भी है।

जेवर हवाई अड्डा, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 25 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और योजनागत प्रक्रिया के बाद साकार हुआ है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तावित यह परियोजना विभिन्न कारणों से लंबित रही। परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ाया।

यह परियोजना इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब सुदृढ़ शासन, दूरदर्शी योजना और सार्वजनिक–निजी सहभागिता (public-private partnership) एक साझा दृष्टि के साथ कार्य करते हैं, तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी वास्तविकता में बदल सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि जेवर हवाई अड्डे के लोकार्पण से पूर्व ही केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत 100 नए हवाई अड्डों तथा 200 नए हेलिपैडों के निर्माण के लिए 29,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जेवर हवाई अड्डा एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होने की क्षमता रखता है और यह पूर्णतः डिजी–यात्रा ऐप के माध्यम से संचालित होगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम अनुभव प्राप्त हो।

विकास के चरण : योजना से वास्तविकता तक

जेवर एयरपोर्ट का विकास चार चरणों में योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिससे यह परियोजना क्रमिक रूप से अपनी क्षमता और सुविधाओं का विस्तार कर सके।

प्रथम चरण के अंतर्गत 3900 मीटर लंबा रनवे,

अत्याधुनिक टर्मिनल–1, वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) टावर तथा आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास किया गया है। टर्मिनल का डिजाइन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को प्रतिबिंबित करता है, जो विकास के साथ विरासत को जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह स्पष्ट करता है कि हवाई अड्डे केवल यात्री टर्मिनल नहीं होते, बल्कि वे व्यापार, पर्यटन, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को गति देने वाले सशक्त माध्यम भी होते हैं।

इस चरण की वार्षिक क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों (12 एमएमपीए) को संभालने की है। करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस अवसंरचना में 48 चेक–इन काउंटर स्थापित किए गए हैं, साथ ही डिजी–यात्रा आधारित बायोमेट्रिक चेक–इन, पेपरलेस यात्रा और तकनीक–संचालित यात्री अनुभव को शामिल किया गया है। प्रारंभिक चरण में यहाँ से प्रतिदिन लगभग 150 उड़ानों के संचालन की संभावना है, जिसमें प्रति घंटे लगभग 30 विमान संचालन (एयरक्राफ्ट मूवमेंट) की क्षमता उपलब्ध होगी। संभावित रूप से यहाँ से प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियाँ जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर अपनी सेवाएँ संचालित करेंगी।

जेवर हवाई अड्डा, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 25 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा और योजनागत प्रक्रिया के बाद साकार हुआ है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तावित यह परियोजना विभिन्न कारणों से लंबित रही। परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ाया।

द्वितीय चरण में दूसरे रनवे और टर्मिनल–2 के जुड़ने से हवाई अड्डे की क्षमता तथा उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे संचालन और अधिक सुदृढ़ बनेगा। इसके बाद तृतीय चरण में कुल चार रनवे और टर्मिनल–3 के निर्माण के साथ इसे बड़े पैमाने पर एक अंतरराष्ट्रीय हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अंततः चतुर्थ चरण में छह रनवे और टर्मिनल–4 के साथ इस हवाई अड्डे की कुल क्षमता लगभग 7 करोड़ (70 एमएमपीए) यात्रियों तक पहुँच जाएगी, जबकि दीर्घकालिक दृष्टि से वर्ष 2050 तक इसे 15 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष की सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा।

लगभग 4,700 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 29,000 करोड़ रुपये है। इस हवाई अड्डे का संचालन Zurich Airport AG द्वारा सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 40 वर्षों तक किया जाएगा, साथ ही इसे नेट–शून्य उत्सर्जन वाले पर्यावरण–अनुकूल हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यह पूरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जिसमें परियोजना को चरणबद्ध ढंग से इस प्रकार तैयार किया गया है कि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य में बढ़ती मांग को भी सहजता से पूरा किया जा सके।

कनेक्टिविटी और रणनीतिक महत्व

जेवर हवाई अड्डे का सबसे बड़ा लाभ इसकी रणनीतिक स्थिति है, जो इसे उत्तर भारत के एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करती है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 85

किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्रीय आवागमन अत्यंत सुगम हो जाता है। नोएडा (लगभग 57 किमी), ग्रेटर नोएडा (लगभग 40 किमी), गुरुग्राम (लगभग 65 किमी) तथा आगरा (लगभग 130 किमी) जैसे प्रमुख शहरों से इसकी निकटता इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से यह हवाई अड्डा एक विस्तृत प्रभाव क्षेत्र को सेवा देने की क्षमता रखता है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस प्रकार यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को वैश्विक हवाई मार्गों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु बन रहा है। इसके संचालन से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव में उल्लेखनीय कमी आएगी, साथ ही व्यापार, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे केवल एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित नहीं किया है, बल्कि एक मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य किया है। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क, प्रस्तावित मेट्रो और रैपिड रेल ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस), दिल्ली–वाराणसी बुलेट ट्रेन का प्रस्तावित स्टेशन–जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी को मात्र 21 मिनट में पूरा करने में सक्षम होगा–तथा सड़क, बस और रेल नेटवर्क का एकीकृत ढांचा, इस व्यापक दृष्टिकोण को साकार करते हैं।

इसके साथ ही, दादरी में मिल रहे समर्पित माल गलियारे (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र में परिवर्तित कर रहे हैं, जहाँ से उत्तर भारत सीधे बंगाल और गुजरात के समुद्री तटों से जुड़ रहा है। इस एकीकृत व्यवस्था के कारण किसानों की उपज और उद्योगों के उत्पाद तेज, विश्वसनीय और कम लागत में देश–विदेश के बाजारों तक पहुँच सकेंगे। रेल, सड़क और वायु परिवहन के इस समन्वित ढांचे ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बना दिया है।

इस प्रकार विकसित कनेक्टिविटी न केवल दिल्ली–एनसीआर पर बढ़ते दबाव को कम करेगी, बल्कि "ट्विन एयरपोर्ट मॉडल" के अंतर्गत हवाई यातायात को संतुलित करते हुए पूरे क्षेत्र में संतुलित और तीव्र विकास को भी गति प्रदान करेगी।

आधुनिक तकनीक, कार्गो और इंफ्रास्ट्रक्चर

जेवर हवाई अड्डे को भारत के सबसे आधुनिक और भविष्य उन्मुख हवाई अड्डों में शामिल किया गया है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश इसे विशिष्ट बनाता है। यहाँ स्थापित इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) कैटेगरी–III प्रणाली के माध्यम से घने कोहरे में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव होगी। डिजी–यात्रा ऐप पर आधारित फेस स्कैन से प्रवेश और चेक–इन की व्यवस्था इसे पूर्णतः

डिजिटल बनाती है, जिससे यात्रियों की प्रक्रिया तेज, पेपरलेस और सहज होगी। इसके साथ ही, AI आधारित सुरक्षा प्रणाली इसे और अधिक सुरक्षित बनाती है। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा जो सौर ऊर्जा के उपयोग पर आधारित है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी जेवर हवाई अड्डा एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। लगभग 30 एकड़ में विकसित कार्गो टर्मिनल, जिसकी लागत करीब 800 करोड़ रुपये है, प्रारंभिक रूप से 2.5 लाख मीट्रिक टन माल की ढुलाई करने में सक्षम होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 57 एकड़ में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब इस क्षेत्र को एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।

इसी के साथ प्रस्तावित 40 एकड़ का मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (MRO) केंद्र इस हवाई अड्डे को और अधिक रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। वर्तमान में भारत के लगभग 85 प्रतिशत विमान अपने रखरखाव के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, जिसे आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। इस स्थिति को बदलने के उद्देश्य से जेवर में एमआरओ सुविधा की स्थापना भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके संचालन से न केवल देश में राजस्व का संरक्षण होगा, बल्कि युवाओं के लिए बड़ी संख्या में कौशल–आधारित रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

आर्थिक प्रभाव और भविष्य

वैश्विक अनुभव बताता है कि हवाई अड्डा आधारित विकास मॉडल पूर्ण रूप से विकसित होने पर क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2–4 प्रतिशत तक योगदान कर सकता है, और जेवर हवाई अड्डा भी आने वाले दशक में इसी दिशा में अग्रसर होने की क्षमता रखता है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है तथा इसे घरेलू और विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से उद्योगों, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी, जबकि पहले जो परिवहन बाधाएँ विकास में अवरोध बनती थीं, वे अब समाप्त होंगी।

इसके माध्यम से लगभग 7 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसका प्रभाव दिल्ली–एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक व्यापक रूप से फैलेगा। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा कृषि निर्यात को नई गति मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री का यह कथन– "हवाई अड्डे केवल किसी देश की मूलभूत सुविधाएँ नहीं होते, बल्कि वे विकास को पंख

देते हैं" इस परियोजना के महत्व को स्पष्ट करता है। वास्तव में, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किसानों को अपनी उपज दूरस्थ बाजारों तक पहुँचाने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वैश्विक अवसरों से जोड़ने तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री की यह अभिव्यक्ति– "नोएडा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए तैयार है"– रेखांकित करती है कि यह क्षेत्र अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त रूप से भाग लेने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार हो चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार की "वन डिवीजन, वन एयरपोर्ट" नीति और समग्र क्षेत्रीय विकास दृष्टि के अंतर्गत इस हवाई अड्डे को एक एरोट्रोपोलिस (Aerotropolis) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ होटल, शॉपिंग मॉल, कार्यालय, लॉजिस्टिक हब और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और शहरीकरण को नई गति मिलेगी, जबकि पर्यटन के क्षेत्र में भी आगरा, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँच अधिक सुगम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और निवेश को प्राथमिकता देकर जिस विकास मॉडल को आगे बढ़ाया है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका सशक्त उदाहरण है। यह परियोजना "आत्मनिर्भर भारत" की उस व्यापक अवधारणा को भी साकार करती है, जिसमें वैश्विक जुड़ाव के साथ घरेलू क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है। अंततः, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि विकास की नई उड़ान है, जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। ◆

मो. : 8750820740

(लेखक विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय हैं)

एआई सिटी और भविष्य का उत्तर प्रदेश

—डॉ. ऋतु दुबे तिवारी

कहा जाता है की डाटा भविष्य का ईंधन है यानि आने वाले भविष्य में उस देश का वर्चस्व होगा जिसके पास अपना डाटा भंडारण और अपनी तकनीक होगी। एआई अब सीमित नहीं है स्वास्थ्य, कला, शिक्षा, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और प्रशासन में डिजिटल तकनीकी आदि लगभग हर क्षेत्र में इसका आधिपत्य बढ़ता जा रहा है। एआई का ज्ञान रखने वाले युवा देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एआई सिटी लखनऊ एवं नोएडा

विकसित करने की योजना पर काम कर रही है इससे राज्य को तकनीकी रूप से मजबूत और सशक्त बनाया जा सकेगा। एआई प्रज्ञा योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य में 30000 करोड़ से अधिक का निवेश डाटा सेंटर और एआई आधारित बुनियादी ढांचे के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन युवाओं में न सिर्फ युवा, विद्यार्थी बल्कि महिलाएं किसान, गांव के मुखिया स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोग ऑपरेटर्स और आम लोग भी शामिल होंगे। यह कौशल निर्माण करने का कार्य न सिर्फ नवाचारों को बढ़ावा देने वाला होगा बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम की तरह याद रखा जाएगा।

समय की मांग

यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया और आधुनिक तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकती है।यह बात स्पष्ट है कि आने वाला समय प्रभावी रूप से आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा टेक्नोलॉजी पर मजबूत पकड़ रखने वाले देश का होगा। आज एआई और डाटा सेंटर आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके हैं और इनके माध्यम से बड़े स्तर पर डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है और स्मार्ट फैसले लेने में मदद मिल रही है।

प्रदेश की डाटा सेंटर नीति के तहत 5 हाइपर स्केल डाटा सेंटर पार्कों का उपयोग शुरू किया जा चुका है। आज सारी सरकारों को यह भली– भांति ज्ञात है कि बिना एआई प्रशिक्षण के देश को स्थायी बेहतरीन सेवा देना संभव नहीं है और वह इस दिशा में कार्य कर रही हैं।

करियर की संभावनाएं

एआई डाटा साइंस, मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग आदि के क्षेत्र में युवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना रहेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर बड़ी कंपनियां आएंगी और लोगों को बिना दूर जाए अपने ही राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इन संभावनाओं में न सिर्फ स्टार्टअप, रिसर्च, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोग और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे, कुल मिलाकर एआई सिटी युवाओं के करियर को नई दिशा देने का काम करेगी।

इस योजना के तहत इन युवाओं में न सिर्फ युवा, विद्यार्थी बल्कि महिलाएं किसान, गांव के मुखिया स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोग ऑपरेटर्स और आम लोग भी शामिल होंगे। यह कौशल निर्माण करने का कार्य न सिर्फ नवाचारों को बढ़ावा देने वाला होगा बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम की तरह याद रखा जाएगा।

भविष्योन्मुखी कदम

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम भविष्य की तरफ देखने वाला कदम रहेगा इस प्रकार की योजना से न सिर्फ कौशल विकास होगा बल्कि रोजगार का भी सृजन किया जा सकेगा,बुनियादी ढांचे पर काम किया जा सकेगा, निवेश किया जा सकेगा और आने वाले समय में यह एक बहुत सशक्त और दूरदर्शी योजना साबित होगी जिसका न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 को टेक्नोलॉजी एआई और डाटा में नए मानक स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा।

आज जिस रणनीति पर काम किया जा रहा है उसमें युवाओं के योगदान का स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सकता है। युवाओं को मुख्यमंत्री ने ज्ञानदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जिसमें उनके आसपास पढ़ रहे कम से कम पांच बच्चों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक बनाने का कार्य किया जाएगा। निःसंदेह 2026 यूपी के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित होगा और आने वाले समय में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र की तरह याद रखा जाएगा। ◆

मो. : 9650450604

(लेखिका शिक्षाविद एवं साइबर विशेषज्ञ, वर्तमान में प्रिंसिपल, मीडिया कॉलेज गाजियाबाद)

रक्षा उत्पादन केंद्र बनता उत्तर प्रदेश

–प्रदीप कुमार गुप्ता

भारत की विगत 11 वर्षों की विकास यात्रा करोड़ों देशवासियों के स्वप्न के साकार होने की यात्रा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करते हुए देशवासियों को गौरवान्वित किया है। जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत आज दूसरे देशों की समृद्धि में भी अपना योगदान दे रहा है। एक ऐसे समय में जब दुनिया के सभी देश ग्लोबलाइजेशन से अलग अपने–अपने हितों को तरजीह दे रहे हैं, भारत भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है। रक्षा क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में हुई देश की प्रगति हमारी सैन्य क्षमताओं को अपने संसाधनों और तकनीक के उन्नयन से मजबूत बना रही है। देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल और प्रतिबद्ध नेतृत्व में पिछले साढ़े आठ वर्षों से देश के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए न केवल स्वयं को, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक लम्बे समय तक देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस, अमेरिका, इजरायल तथा विभिन्न यूरोपीय देशों पर निर्भर रहा है। इसमें देश का बहुत अधिक पैसा खर्च होता था। जो धन देश के विकास में लगना चाहिए था, वह विदेश से रक्षा उत्पादों की खरीद में व्यय हो जाता था। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदृष्टि और प्रेरणादायी नेतृत्व से इस स्थिति में परिवर्तन आया है। अब भारत रक्षा उत्पादों का आयातक नहीं, बल्कि उनके निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो रहा है। पिछले एक दशक में देश रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सकल निर्यातक बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2013–14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपये से 23 गुना बढ़कर वर्ष 2024–25 में 21 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में बनी ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य हथियारों ने सीमापार के आतंकी ठिकानों को जिस सटीकता से नेस्तनाबूद किया, भारत के

इस रणकौशल से दुनिया भी अचम्भित रह गई। अब इसी ब्रह्मोस मिसाइल का नया पता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ब्रह्मोस अब नवाबों और तहजीब के शहर लखनऊ में बनने लगी है। अब लखनऊ दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि तहजीब और अमन के साथ ही हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे सटीक और तीव्र गति वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल दुश्मनों के प्रति देश की सेनाओं की प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती का उदाहरण है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मरकवा नदी के संयुक्त नाम पर बनी ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। यह भारत और रूस की बेमिसाल दोस्ती और दो अलग–अलग संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने फरवरी, 2018 में देश में उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में 02 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इनके माध्यम से देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने की परिकल्पना की गयी। उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के 06 नोड्स अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में तेजी से आकार ले रहे हैं। इन नोड्स की विशेष

बात यह है कि इन्हें तीव्र और आसान आवागमन तथा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मौजूदा एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस वे के संरेखण में स्थापित किया गया है। इन नोड्स में प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं जैसे विद्युत एवं जलापूर्ति, सीवेज सिस्टम, अपशिष्ट उपचार, आन्तरिक सड़क क्षेत्र में जल निकासी, इण्टीग्रेटेड ऑफसाइट फायर स्टेशन, बाउण्ड्री वॉल आदि का निर्माण किया जा रहा है। देश के रक्षा उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देने के क्रम में उत्तर प्रदेश में निजी रक्षा निर्माताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित रक्षा औद्योगिक नीति लागू है।

उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत उद्योगों एवं संस्थानों के साथ लगभग 170 एम.ओ.यू. किये गए हैं। इनमें 28 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा लगभग 50 हजार लोगों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं सृजित हुई हैं। उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विभिन्न नोड्स में विस्फोटक, गोला बारूद, प्रणोदन प्रणाली, मध्यम कैलिबर इन्फैण्ट्री हथियार के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म, बुलेटप्रूफ जैकेट, विशेष कपड़े, छोटे हथियार, ड्रोन, काउण्टर ड्रोन, सटीक उपकरण, रडार, मिसाइल सिस्टम, रक्षा पैकेजिंग जैसे हथियार एवं सहायक उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स प्रदेश को रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में देश का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने की ओर एक नई शुरुआत है। यह हमारे प्रदेश के लिए अत्यन्त सुनहरा अवसर है कि वह देश की विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के अभियान में अपनी सशक्त भूमिका निभाकर राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। मुख्यमंत्री पूरी गम्भीरता से प्रदेश को विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश बनाए जाने के प्रति समर्पित भाव से लगे हुए हैं।

इसी वर्ष मई माह में डिफेन्स कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एयरोस्पेस एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत् प्रयासों से इस फैसिलिटी का निर्माण मात्र 40 महीनों में ही कर लिया गया। इसके साथ ही टाइटेनियम एण्ड सुपर एलॉय मैटेरियल प्लाण्ट का उद्घाटन भी किया गया। यह दोनों संयन्त्र उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश व दुनिया के प्रमुख रक्षा उत्पादन केन्द्र बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहे हैं। इसके साथ ही लखनऊ नोड में अन्य रक्षा उत्पादों के केन्द्रों का शिलान्यास हुआ है। इनमें स्ट्रेटजिक पाउडर मैटलर्जी फैसिलिटी, पी.टी.सी. रिसर्च एंड डेवलपमेण्ट सेण्टर आदि शामिल हैं। यह सभी हमारी सेनाओं की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश

को दुनिया के टॉप डिफेन्स प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह कार्य मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, सेटेलाइट आदि में प्रयुक्त होने वाले पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। इस दिशा में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्ट्रैटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का निर्माण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण से राज्य के औद्योगिक विकास के जिस नए युग का श्रीगणेश हुआ है, आने वाले समय में यह प्रदेश की नई पहचान भी बनेंगे। डी.आर.डी.ओ., पी.टी.सी., एल. एण्ट टी., गोदरेज, बी.डी.एल., आदि इकाइयां कॉरिडोर में निवेश कर रही हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह रोजगार के भी अनेक अवसरों का सृजन कर रहा है। यह पूरा क्षेत्र एक ग्रोथ सेण्टर के रूप में उभर रहा है। यहां डिफेन्स उत्पादों से जुड़ी सहायक एम.एस.एम.ई. इकाइयों की स्थापना भी हो रही है। 'मेक इन इण्डिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य से केन्द्र व प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। दुनिया के सैन्य बाजार में मौजूद अपार सम्भावनाओं के दोहन के दृष्टिगत भारत को भी अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करना जरूरी है। तभी हम वैश्विक सैन्य बाजार की क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। देश के विकास का रास्ता विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश से जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में समन्वित रूप से प्रयास भी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं को ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहा है। कानपुर में रक्षा सेनाओं के लिए गोला–बारूद बनाने का केन्द्र स्थापित किया गया है। अमेठी में ए.के.–203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। सशक्त भारत सुरक्षित भारत के प्रधानमंत्री के विजन का रास्ता स्वदेशी हथियारों के देश में निर्माण से ही जाता है। नया उत्तर प्रदेश सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुका है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइन्सेज, लखनऊ प्रदेश पुलिस और भावी पीढ़ी को न्यू एज कोर्सेस और तकनीक का ज्ञान करा रहा है। आने वाला समय साइबर युद्ध का है। जिस देश की सायबर सिक्योरिटी क्षमता जितनी मजबूत, सुदृढ़ और अभेद्य होगी, वह उतना ही जंग में प्रभावी होगा। हाल ही में देश की सेनाओं द्वारा संचालित किया गया ऑपरेशन सिंदूर साइबर युद्ध के रूप में ही लड़ा गया। भारत ने इसमें अपनी श्रेष्ठता साबित की। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइन्सेज में साइबर युद्ध के

आयाम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह नेशनल सिक्योरिटी की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश का यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा को नए आयाम दे रहा है।

लखनऊ में भारतीय नौसेना की अदम्य शौर्यगाथाओं और हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता के जीवन्त प्रतीक के रूप में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। लखनऊ अब केवल तहजीब का शहर ही नहीं रहा, यह तकनीक, उद्योग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण केन्द्र बन चुका है। प्रदेश में स्थापित डिफेंस कॉरिडोर के 06 नोड न केवल देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों की स्किल बढ़ाते हुए उन्हें व्यापक स्तर पर रोजगार से भी जोड़ने का माध्यम बन रहे हैं। यहां लगने वाले उद्योग और सहायक एम.एस.एम.ई. इकाइयां प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहायक हो रहे हैं। लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीएसटी का 40 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है।

लखनऊ दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि तहजीब और अमन के साथ ही हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे सटीक और तीव्र गति वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल दुश्मनों के प्रति देश की सेनाओं की प्रतिरोधक क्षमता की मजबूती का उदाहरण है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मरकवा नदी के संयुक्त नाम पर बनी ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। यह भारत और रूस की बेमिसाल दोस्ती और दो अलग–अलग संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है।

वह दिन अब दूर नहीं जब देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका में होगा। विगत लगभग साढ़े आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किए गए समग्र प्रयासों से उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश, उद्यम प्रदेश और एक्सप्रेस–वे प्रदेश के रूप में पहचान बनी है। अब हमारा प्रदेश देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले हथियारों के निर्माणकर्ता प्रदेश के रूप में पहचान स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है। आइए हम भी इस यात्रा के सहभागी बनें। ◆

मो. : 7705800992

(लेखक मुख्यमंत्री सूचना परिसर में फीचर लेखक (सूचना अधिकारी) हैं)

आत्मनिर्भर होता ग्रामीण उत्तर प्रदेश

—डॉ. शिव राम पाण्डेय

महात्मा गाँधी जी ने देश के स्वतंत्र होने पहले ही भारत में ग्राम गणतंत्र की परिकल्पना की थी। हलांकि देर से सही सरकार ने बीसवीं शताब्दी में ही पंचायत राज का कानून पारित कर देश में त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था लागू किया। इस कानून के माध्यम से लोकतांत्रिक विधि से जिला पंचायत, नगर पंचायत विकास खण्ड पंचायत और ग्राम पंचायतों के गठन विधान बना। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में अलग पंचायत मंत्रालय भी बनाया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद गाँव के विकास लिए ग्राम पंचायतों को ही अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं को बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को सीधे बजट दिया जाने लगा जिससे रोजगार सृजन विकास कार्यों में तेजी आई है और ग्रामीण भरत आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हो चला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अब हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालयों की व्यवस्था कर दिया है।

राज्य सरकार ग्राम गणतंत्र को अधिक सशक्त बनाने के लिए अब ग्राम पंचायतों को और अधिक साधन और शक्ति संपन्न बनाती जा रही है। ग्राम विकास अधिकारियों की व्यवस्था तो थी ही अब ग्राम सचिवालयों के बन जाने के बाद उसको संचालित करने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अब प्रत्येक ग्राम सचिवालय में डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंध कर दिया है जिससे युवा ग्रामीण अपने घर पर ही रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें और सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। सरकार ने अब ग्राम सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने और उनमें संशोधन आदि की सुविधा भीउपलब्ध कराने जा रही है।

1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। ग्रामीणों को आधार सेवाओं के लिए अब ब्लॉक और शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नया आधार बनवाने से लेकर आधार अपडेट और प्रमाणीकरण तक की सुविधाएं सीधे गांव में ही मिल सकेंगी ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) ने पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी (ईए) आईडी भी निर्गत कर दी है, जिससे आधार सेवाओं का संचालन पूरी तरह अधिकृत और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

इस नई व्यवस्था से आधार नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और ऑनलाइन सुविधाएं सरल और सुगम होगी। इससे ग्रामीणों का सीधा जुड़ाव सरकारी योजनाओं से सुनिश्चित होगा। साथ ही आधार से जुड़ी सेवाओं में होने वाली परेशानियां समाप्त होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की योजना है।

यह पहल न केवल डिजिटल सशक्तिकरण को मजबूती देगी, बल्कि गांवों में ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध

कराकर शासन की गांव–विकास की सोच को भी साकार करेगी। उइसी प्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रही है जिससे युवा घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस डिजिटल लाइब्रेरी में वाई–फाई, एलईडी, कैमरे, आधुनिक फर्नीचर की सुविधा से लेकर वीडियो, ऑडियो लेक्चर और क्विज सारी सुविधाएं पा सकेंगे।

यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को देश के बड़े कोचिंग और अध्ययन केंद्रों जैसी सुविधाएं उनके अपने गांव में उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी में वाई–फाई, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम के साथ–साथ किताबों और डिजिटल कंटेंट की समृद्ध व्यवस्था होगी। ई–बुक्स, वीडियो और ऑडियो लेक्चर, क्विज और लाखों डिजिटल शैक्षणिक सामग्री के जरिए ग्रामीण युवा अब अपने गांव में रहकर ही उच्च स्तरीय तैयारी कर सकेंगे।

1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है। ग्रामीणों को आधार सेवाओं के लिए अब ब्लॉक और शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नया आधार बनवाने से लेकर आधार अपडेट और प्रमाणीकरण तक की सुविधाएं सीधे गांव में ही मिल सकेंगी ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

यह विकसित भारत की दिशा में युवाओं को बराबरी का अवसर देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 2 लाख रुपये की पुस्तकें, 1.30 लाख रुपये के आईटी उपकरण और 70 हजार रुपये के आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। योगी सरकार की यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और विकसित भारत की दिशा में युवाओं को बराबरी का अवसर देने वाला मजबूत कदम मानी जा रही है। सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा और युवा रोजगार व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक सक्षम बनेंगा।

कचरे से कंचन बनाने का अभियान

देश के प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने भारत की

स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को अमृत वर्ष घोषित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वयं हाथ में झाड़ू उठा कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने दो कदम आगे बढ़ते हुए सफाई से निकलने वाले कचरे को कंचन बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान से निकालने वाले कचरे को ग्राम पंचायतों की आमदनी का जरिया बना दिया गया है।

यानी 'आम के आम और गुठलियों के भी दाम'। उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से जहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है वहीं गाँव में स्वच्छता अभियान के कारण बीमारियों और महामारियों का खतरा भी कम हुआ है। यही नहीं, स्वच्छता अभियान से निकले वाले कचरे को कमाई का जरिया बना दिया गया है।

अब उत्तर प्रदेश के गांव हाईटेक हो रहे हैं। सफाई से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाई जा रही हैं। राज्य इस प्रकार के कचरे से अब तक 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा चुकी है।

राजधानी लखनऊ के साथ ही रामपुर, अमेठी, ललितपुर और एटा में भी प्लास्टिक कचरे का अभिनव प्रयोग किया गया है। इस अभिनव प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है इसके साथ ही विकास का नया मॉडल भी विकसित हो रहा है।

यही नहीं, अब कूड़े से कमाई भी शुरू हो गई है है।

ग्राम पंचायतों में घर–घर कूड़ा संग्रहण करना शुरू किया गया है और इस कचरे से जैविक खाद का उत्पादन शुरू कर दिया गया है जिससे अब तक, तीन करोड़ रुपये से अधिक की आय हो चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वेस्ट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत प्रदेश के हर गांव को स्वच्छ बनाने का महाभियान शुरू किया गया है।

इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश के गांव स्वच्छता और नवाचार की नई पहचान गढ़ रहे हैं। प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण, घर–घर कूड़ा संग्रहण कर उससे खाद निर्माण और आय सृजन के अभिनव प्रयोगों ने प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को हाईटेक बना दिया है। राजधानी लखनऊ समेत रामपुर, अमेठी, ललितपुर और एटा में प्लास्टिक कचरे से अब तक 75 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की जा चुकी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का नया मॉडल पेश कर रही हैं।

देश के प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को अमृत वर्ष घोषित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। स्वयं हाथ में झाड़ू उठा कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की थी मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने दो कदम आगे बढ़ते हुए सफाई से निकलने वाले कचरे को कंचन बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान से निकलने वाले कचरे को ग्राम पंचायतों की आमदनी का जरिया बना दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में घर–घर से कूड़ा संग्रहण शुरू कर वर्मी खाद का उत्पादन किया जा रहा है। इस पहल से अब तक 3 करोड़ रुपये से अधिक की आय सृजित हो चुकी है। वहीं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से 29 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई की गई है। इस योजना के तहत पंचायतीराज विभाग प्रदेश में 'वेस्ट टू वेल्थ' मॉडल पर काम कर रहा है।

पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ गांव महाभियान के तहत कूड़े को संसाधन में बदला जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग कर सड़क निर्माण, जैविक कचरे से खाद उत्पादन और पंचायतों की आय बढ़ाने के ये प्रयोग प्रदेश के हर गांव को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस योजना के जरिए प्रदेश के हर गांव में अभिनव प्रयोग किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को नवाचार के माध्यम से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहाहै। गांव–गांव स्वच्छता अभियान के साथ प्लास्टिक वेस्ट के यूटिलाइजेशन से न केवल पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, बल्कि करोड़ों रुपये की आय भी सृजित हो रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस नयी पहल से ग्राम पंचायतों में साफ सफाई तो रहेगी ही, वातावरण भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी तो जैविक कृषि को बढ़ावा मिलने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ◆

मो. : 9305264002

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं कृषि विशेषज्ञ हैं)

यूपी पुलिस दुनिया के लिए रोल मॉडल

—राघवेंद्र प्रताप सिंह

कानून और व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा और प्रगति की बैकबोन है और इस समय योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस प्रणाली को विश्वस्तरीय मानकों तक ले जाने की दिशा में कार्यवाही कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, फोरेंसिक लैब्स का

आधुनिकीकरण, अपराध जांच में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका, रियल टाइम बेस पर खुफिया सूचनाओं की जानकारी की सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जा रही है। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर पुलिस की तैनाती के मानकों पर भी प्रदेश सरकार द्वारा संवेदनशीलता से सोचा जा रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन–2025 'पुलिस मंथन' का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपने सम्बोधन में यूपी पुलिस के अब तक के कार्य, सुधार और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा गया कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन और कानून–व्यवस्था की छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों से उत्तर प्रदेश को आज देश–दुनिया में एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है और परिवर्तन की यह पहचान जनता के अनुभवों से सिद्ध होती है, न कि आत्मप्रशंसा से। इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग का विजन साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक पुलिसिंग के हर स्तर पर व्यापक बदलाव हुए, भर्ती, प्रशिक्षण, अवसंरचना, तकनीक, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक क्षमता, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, UP–112, सेफ सिटी मॉडल, महिला पुलिस भर्ती, और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की दिशा में निर्णायक प्रगति की गई है। पहले जहां प्रशिक्षण क्षमता सीमित थी,

वहीं आज बड़े पैमाने पर 60,000 से अधिक आरक्षियों का प्रशिक्षण प्रदेश के अन्दर ही कराया जा रहा है। 75 जनपदों में साइबर थाने, 12 एफएसएल लैब और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जैसे संस्थागत बदलाव प्रदेश की नई सोच को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि कानून और व्यवस्था पर प्रभावी कार्यवाही प्रगति के नए अवसर को खोलेगी। आज यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास व सम्मान का भाव स्थापित कर रही है। पुलिस की भूमिका अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रो–एक्टिव और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग की ओर बढ़ चुकी है। उनके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने, नवाचार अपनाने और समयबद्ध व बिंदुवार कार्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अंत में मुख्यमंत्री योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह दो दिवसीय पुलिस मंथन कार्यक्रम नीति, रणनीति और बेहतर क्रियान्वयन के जरिए समग्र पुलिसिंग को नई दिशा देगा और यूपी पुलिस अपने कार्यों को उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न सत्रों की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस की परिवर्तनकारी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने भर्ती, प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना, तकनीक–आधारित नागरिक सेवाओं, फॉरेंसिक सुदृढ़ीकरण, साइबर पुलिसिंग, मिशन शक्ति केन्द्र, विशेष इकाइयों के गठन तथा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य प्रत्येक सत्र से स्पष्ट उत्तरदायित्व, निर्णयों की स्पष्ट टाइमलाइन और ठोस परिणाम सुनिश्चित करना है, ताकि यह मंथन कक्षों से निकलकर फील्ड में दिखाई दे और नागरिकों तक बेहतर, responsive एवं citizen-first police service पहुँचे। सम्मेलन के प्रथम दिवस कुल 07 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक सत्र के 07 नोडल वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया । बढ़ते अपराधों की जटिलता, साइबर अपराधों में वृद्धि तथा नागरिकों की त्वरित न्याय की अपेक्षाओं के दृष्टिगत पुलिसिंग को अधिक डेटा–आधारित, वैज्ञानिक एवं नागरिक–केंद्रित बनाये जाने, CCTNS के माध्यम से पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर एवं विवेचना से संबंधित डेटा का एकीकरण एवं नई न्याय संहिताओं के अंतर्गत

ईएफआईआर, जीरो एफआईआर, ई समन एवं ई साक्ष्य जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस तंत्र द्वारा प्रभावी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कारागारों का डिजिटलीकरण करने, डिजिटल तकनीक से पारदर्शिता, सुरक्षा, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, बंदियों का सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायालय में 50,000 से अधिक गवाही कराये जाने, AI आधारित सीसीटीवी निगरानी, ई–मुलाकात, हेल्थ ए.टी.एम., डिजिटल लाइब्रेरी, समय पूर्व रिहाई सॉफ्टवेयर, ई–अभिरक्षा प्रमाणपत्र आदि नवाचारों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किए हैं।

उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग के अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं एवं उसके निवारण, उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों एवं उनके आश्रित परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा एवं जागरूकता हेतु वामा सारथी द्वारा किये जा रहे सराहनीय प्रयासों एवं प्रचलित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, भारत सरकार के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म– i–GOT पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के पुलिस बल को प्रशिक्षण कोर्स कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था मजबूत विजन के साथ आगे बढ़ रही है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए 84,000 पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण :

साइबर धोखाधड़ी और हाई–टेक अपराध के मामलों में वृद्धि के साथ–साथ डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस बल को तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए 84,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से 84,705 पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध जांच और रोकथाम में प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन घोटालों और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करना है। सरकार ने साइबर

अपराध नियंत्रण तंत्र को चरणबद्ध तरीके से मजबूत करने का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें बताया गया कि 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में केवल दो साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन योगी सरकार द्वारा साइबर पुलिसिंग के व्यवस्थित विस्तार के बाद, 6 फरवरी, 2020 को 16 जोनल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके बाद 14 दिसंबर, 2023 को 57 जिला स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला पुलिस स्टेशन में प्रशिक्षित कर्मचारियों वाली एक साइबर सेल है। सरकार ने साइबर अपराध रोकथाम के प्रमुख स्तंभ के रूप में जन जागरूकता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, नागरिकों को आम ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 65,966 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की क्षमता 20 से बढ़ाकर 50 सीटें कर दी गई है और अब यह सेवा 24x7 उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने किया यक्ष ऐप का लोकार्पण :

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यक्ष ऐप का लोकार्पण किया गया। 'यक्ष ऐप'– AI और Big Data Analysis की सहायता से तैयार किये गये बीट बुक का डिजिटल स्वरूप है। इसके माध्यम से बीट पर अपराध, अपराधियों तथा संवेदनशील क्षेत्रों का समग्र डाटा उपलब्ध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस बल को तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए 84,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साइबर क्राइम ट्रेनिंग पोर्टल के माध्यम से 84,705 पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध जांच और रोकथाम में प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

होगा, जिससे पुलिस कार्यवाही अधिक तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं लक्षित रूप में की जा सकेगी। यह ऐप बीट कर्मियों के रोजमर्रा के कार्यों को आसान, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में भी मददगार होगा। यूपी की पुलिसिंग अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह पुलिसिंग पहले से ज्यादा एडवांस हैं। यूपी पुलिस की कार्यशैली एक तरह से अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की पुलिस जैसी हो जाएगी। अब थानों में मोटे–मोटे रजिस्टरों के बोझ घट जाएंगे। दीवान जी को घंटों अब क्रिमिनल की कुंडली नहीं खंगालनी पड़ेगी। सिपाही की बीट ड्यूटी लगाने में भी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। यह सब कुछ अब ऐप पर आ गया है। सिपाही भी अब पहले से ज्यादा एडवांस होंगे। वह ऐप पर क्रिमिनल से जुड़ी हर जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इससे पुलिस को अपराध से निपटने में बड़ी सहायता मिलेगी।

ऐप की खासियत : प्रदेश में किसी भी जनपद में जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को करने वाले अपराधियों का पता थानावार ऐप पर दर्ज रहेगा। बीट का सिपाही प्रत्येक अपराधी का सत्यापन उसके मोहल्ले और गांव में जाकर करेंगे और ऐप पर जानकारी भरेंगे। अब बीट के अपराधी की जिम्मेदारी बीट के सिपाही पर होगी। अपराधी की लोकेशन इस ऐप पर अपडेट होती रहेगी। इससे माफिया, हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर, वाण्टेड, पुरस्कार घोषित की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। सीसीटीएनएस पर दर्ज मुकदमे में आरोप पत्र लगने के पश्चात अपराधी से संबंधित हर जानकारी ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगी। इससे पुलिस को यह मदद मिलेगी कि संबंधित व्यक्ति कैसा अपराधी है। सजायाफ्ता अपराधियों की निगरानी और हिस्ट्रीशीटर की निगरानी आसान होगी। लाइसेन्सी शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन भी हो सकेगा। ऐप में अभियुक्तों की श्रेणीवार कलर कोडिंग की व्यवस्था है। ◆

मो. : 9415650340

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता

–डॉ. दीपक कोहली

आज का समय पूर्णतः डिजिटल युग बन चुका है। हमारी दिनचर्या, कामकाज, पढ़ाई, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, संचार, सब कुछ अब संजालित साधनों पर निर्भर है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट के बिना जीवन कल्पना से भी कठिन लगता है। जैसे–जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, वैसे–वैसे डिजिटल दुनिया में खतरे भी बढ़ते चले गए हैं। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा आज केवल तकनीकी शब्द नहीं रहा, बल्कि समाज, व्यक्ति और राष्ट्र–सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन खतरों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर कील–कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं।

डिजिटल युग में मानव जीवन जिस तीव्र गति से परिवर्तित हुआ है, वह इतिहास के किसी भी अन्य काल की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और गहन है। आज मनुष्य का लगभग हर कार्य किसी न किसी रूप में डिजिटल साधनों पर निर्भर हो चुका है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, कृषि, प्रशासन, शोध–ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ न बनाई हो। यह बदलता परिवेश जहाँ अनेक सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं इसके पीछे छिपे संभावित खतरे भी उतने ही गंभीर हैं। यही कारण है कि आधुनिक समय में साइबर सुरक्षा जीवन का अपरिहार्य अंग बन चुकी है। यह केवल मशीनों की सुरक्षा नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक अस्तित्व की सुरक्षा है।

डिजिटल दुनिया में डेटा का मूल्य पहले कभी इतनी अधिक नहीं रहा। आज डेटा को आधुनिक युग का ईंधन कहा जाने लगा है। यह डेटा किसी व्यक्ति के निजी विवरणों से लेकर किसी संस्था के गोपनीय दस्तावेजों और देशों की संवेदनशील सूचनाओं तक फैला हुआ है। साइबर अपराधियों के पास ऐसे उपकरण और तकनीकी कौशल मौजूद हैं जिनसे वे डिजिटल ताले खोलने में सक्षम होते जा

रहे हैं। कई बार एक सामान्य–सी गलती–जैसे किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देना, कमजोर पासवर्ड का प्रयोग करना, या सार्वजनिक वाई–फाई का उपयोग करना–पूरी डिजिटल पहचान को जोखिम में डाल सकती है। ऐसे उदाहरणों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती जा रही है।

साइबर अपराधों का दायरा आज बहुत बड़ा हो गया है। पहले जहाँ केवल ईमेल धोखाधड़ी या सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना ही प्रमुख समस्याएँ थीं, वहीं अब रैनसमवेयर, फिशिंग, स्मिशिंग, बैकडोर अटैक, कीलॉगिंग, पहचान चोरी, डेटा लीक, डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमले बेहद आम हो गए हैं। इन हमलों का प्रभाव केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन तक को प्रभावित कर सकता है। भारत सहित कई देशों में साइबर अपराध के मामलों में दोगुनी से अधिक वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि डिजिटल सेवाओं का उपयोग जितना बढ़ रहा है, उतने ही नए रास्ते अपराधियों को मिल रहे हैं।

डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा की जिंदगी को जितना सरल बनाया है, उतना ही यह धोखाधड़ी के लिए एक आसान लक्ष्य भी बन गया है। आज अधिकांश लोग यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड और वॉलेट का उपयोग करते हैं। यह सुविधा तेज, सस्ती और सुरक्षित है, लेकिन तभी जब उपयोगकर्ता सावधान हो। धोखेबाज नकली कॉल, भ्रामक वेबसाइट, असली जैसे दिखने वाले ऐप और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर लोगों से गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कई बार वे यह दिखाते हैं कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करना है या कोई भारी इनाम मिला है। ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से वे उपयोगकर्ता को भ्रमित कर उसकी आर्थिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर देते हैं। यह समस्या गाँवों और छोटे कस्बों तक पहुँच गई है जहाँ लोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग तो करते हैं, पर साइबर जोखिमों के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होते।

साइबर सुरक्षा केवल पैसे या डिवाइस की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ी है। सोशल मीडिया पर हम बहुत सी निजी जानकारी साझा कर देते हैं—जैसे यात्राओं के विवरण, परिवार के सदस्यों की तस्वीरें, दैनिक गतिविधियां और व्यक्तिगत विचार। ये सब हमारे डिजिटल निशान का हिस्सा होते हैं। यदि यह गलत हाथों में पहुँच जाएं तो इसका उपयोग धमकाने, प्रताड़ित करने, ब्लैकमेल करने, फर्जी पहचान बनाने, अफवाह फैलाने या सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने में किया जा सकता है। आज डीपफेक तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे की नकली वीडियो तैयार करना इतना आसान हो चुका है कि अक्सर सही और गलत में अंतर करना सामान्य उपयोगकर्ता के लिए कठिन हो जाता है।

साइबर खतरे बच्चों और किशोरों के लिए और भी संवेदनशील हो जाते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल प्लेटफॉर्म और चैट सुविधाएं कई बार उन्हें अनजान व्यक्तियों से जोड़ देती हैं। कुछ लोग बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करने, गलत सामग्री दिखाने या उनसे निजी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बच्चे अक्सर इन खतरों को पहचान नहीं पाते, इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों को डिजिटल व्यवहार, साइबर शिष्टाचार और सुरक्षित उपयोग के विषय में लगातार मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। आज डिजिटल पैरेंटिंग उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितनी वास्तविक जीवन में अभिभावक की भूमिका।

डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा की जिंदगी को जितना सरल बनाया है, उतना ही यह धोखाधड़ी के लिए एक आसान लक्ष्य भी बन गया है। आज अधिकांश लोग यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड और वॉलेट का उपयोग करते हैं। यह सुविधा तेज, सस्ती और सुरक्षित है, लेकिन तभी जब उपयोगकर्ता सावधान हों। धोखेबाज नकली कॉल, भ्रामक वेबसाइट, असली जैसे दिखने वाले ऐप और सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर लोगों से गुप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कई बार वे यह दिखाते हैं कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करना है या कोई भारी इनाम मिला है। ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से वे उपयोगकर्ता को भ्रमित कर उसकी आर्थिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर देते हैं।

डिजिटल दुनिया में हर गतिविधि का एक निशान रह जाता है। कोई वीडियो देखने से लेकर किसी वेबसाइट पर जाने, ऑनलाइन खरीदारी करने या केवल किसी विषय को खोजने तक—हर चीज कहीं न कहीं दर्ज होती है। यह जानकारी तकनीकी रूप से उपयोगी तो है क्योंकि इससे सेवाएं बेहतर बनती हैं, पर दूसरी ओर यह हमारी गोपनीयता को खतरे में भी डाल सकती है। बड़ी तकनीकी कंपनियां उपभोक्ताओं के व्यवहार का विश्लेषण कर अत्यंत सटीक विज्ञापन और सेवाएं तैयार करती हैं। इससे सुविधा तो मिलती है, पर साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि किसी व्यक्ति की पसंद, आदतें, मनोविज्ञान और निर्णय तक किसी कंपनी के लिए कितने हद तक ज्ञात होने चाहिए। इसी कारण गोपनीयता का मुद्दा आज वैश्विक बहस का विषय बन गया है।

साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी उपायों से नहीं, बल्कि जागरूकता से भी मजबूत होती है। एक साधारण उपयोगकर्ता अपनी डिजिटल सुरक्षा खुद काफी हद तक सुनिश्चित कर सकता है यदि वह कुछ सामान्य नियमों का पालन करे—जैसे मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, संदिग्ध लिंक से दूर रहना, दो—स्तरीय सत्यापन सक्षम करना, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करना, असुरक्षित वाई—फाई से बचना और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निजी जानकारी साझा न करना। कई देशों में स्कूलों और कॉलेजों में भी साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि युवा शुरुआत से ही सुरक्षित डिजिटल आदतें विकसित कर सकें।

साइबर सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जब किसी देश की बिजली प्रणाली, सैन्य संचार, परिवहन नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवाएँ और बैंकिंग डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हों, तो उन पर साइबर हमला किसी युद्ध से कम नहीं होता। इसी कारण कई देश अब साइबर सेना, साइबर कमांड और डिजिटल रक्षा व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। भारत में भी साइबर सुरक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है, नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं और विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में संभावित खतरों से देश को सुरक्षित रखा जा सके।

डिजिटल प्रौद्योगिकी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर खतरे भी विकसित हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग अब केवल अच्छे कार्यों के लिए नहीं, बल्कि अपराधों के लिए भी होने लगा है। एआई की मदद से किसी पर साइबर हमला करना अधिक सटीक, तेज और पहचान से परे हो सकता है। भविष्य में स्मार्ट उपकरण, स्वचालित वाहन, चिकित्सा उपकरण और घरेलू सिस्टम भी साइबर हमलों के लक्ष्य बन सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा को केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य की अनिवार्यता के रूप में समझना होगा। डिजिटल युग ने मनुष्य को अपार संभावनाएँ दी हैं, पर यह संभावनाएँ एक सुरक्षित ढांचे में ही फल–फूल सकती हैं। यदि हम तकनीक को समझदारी से उपयोग करें, जोखिमों को पहचानें, सही आदतें अपनाएँ और निरंतर जागरूक रहें, तो डिजिटल दुनिया एक सुविधाजनक, सुरक्षित और उपयोगी स्थान बन सकती है। साइबर सुरक्षा का मूल संदेश यही है कि तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाए, धोखे का माध्यम नहीं।

अंततः साइबर सुरक्षा केवल किसी खतरे से बचाव भर नहीं है, यह हमारे डिजिटल भविष्य की रीढ़ है। यह समाज के विश्वास, देश की स्थिरता और व्यक्ति की गोपनीयता का संरक्षण है। तकनीक हमें जितनी सुविधा देती है, उतनी ही समझदारी और सावधानी की अपेक्षा भी रखती है। यदि हम सभी अपने दैनिक जीवन में संजालित सावधानी को आदत बना लें, तो हम न केवल स्वयं सुरक्षित रहेंगे, बल्कि एक सुदृढ़, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देंगे। ◆

मो. : 6389005559

(लेखक विशेष सचिव लो.नि.वि. हैं)

नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का मिशन

—सुनील सिंह

नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति' अभियान सिर्फ सरकारी योजना न बनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का एक मिशन बन गया है। महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली योगी सरकार ने पिछले पांच सालों में बता दिया है कि प्रदेश की महिलाएं और बच्चियां न तो निराश्रित हैं और न ही अबला हैं। उनके साथ होने वाले प्रत्येक दुर्व्यवहार के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनकी शिक्षा और स्वावलंबन की पूरी जिम्मेदारी भी उठाएगी।

मिशन शक्ति 5.0, वर्ष 2020 में शुरू किए गए अभियान का पांचवां चरण है। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ जोड़कर इसे जनांदोलन बना दिया है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन लखनऊ में 'मिशन शक्ति–5.0' का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यह केवल कानून व्यवस्था या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नेतृत्व विकास और परिवार कल्याण जैसे विविध क्षेत्रों को एकीकृत रूप में साथ लेकर चलाया जा रहा है। अभियान की थीम **'सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश'** के जरिये महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन का मार्ग प्रशस्त होना सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत राज्य में पुलिस व्यवस्था, हेल्पलाइन, शिक्षा संस्थानों और पंचायतों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से महिलाओं तक जागरूकता,

सहायता और योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है ताकि वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

सामाजिक भागीदारी बढ़ाने को जागरूकता

मिशन शक्ति के चार चरण पहले ही सफलता पूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। पांचवें चरण के जरिये और व्यापक बदलाव की उम्मीद है। प्रदेश में महिला अपराध मामलों के निस्तारण की दर बढ़ी है, जिससे महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को टेक–होम राशन प्लांट्स, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसकी सफलता के लिए सरकार ने अभियान से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने और उसकी भागीदारी बढ़ाने की पहल की है। सरकार का मानना है कि समाज की सभी इकाइयां एकजुट होती हैं तो महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का सपना साकार किया जा सकता है, जिससे सुरक्षित, समान और समृद्ध प्रदेश की स्थापना संभव होगी। समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत पंचायत स्तर से लेकर शहरी इलाकों तक जागरूकता फैलाने का लक्ष्य तय किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों, समाज–सेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अभियान के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और आत्मरक्षा प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, और 181 की जानकारी गांव–गांव तक पहुंचाई जा रही है।

लखनऊ में 'मिशन शक्ति–5.0' का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यह केवल कानून व्यवस्था या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, नेतृत्व विकास और परिवार कल्याण जैसे विविध क्षेत्रों को एकीकृत रूप में साथ लेकर चलाया जा रहा है। अभियान की थीम 'सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' के जरिये महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन का मार्ग प्रशस्त होना सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत राज्य में पुलिस व्यवस्था, हेल्पलाइन, शिक्षा संस्थानों और पंचायतों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से महिलाओं तक जागरूकता, सहायता और योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है ताकि वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

मिशन शक्ति 5.0 नए अंदाज में

मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नए स्तर पर पहुंचाने के लिए कई नवीन उपक्रम शुरू किए हैं। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश के 1,647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं को त्वरित सहायता, सुरक्षा और परामर्श मिलेगा। महिला पुलिस बल की सक्रियता बढ़ाते हुए 44,177 महिला पुलिस कर्मियों को 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों में तैनात

किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। पिंक बूथ, महिला हेल्पलाइन 1090 और सेल्फ–डिफेंस ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के लिए भी तैयार किया जा सके। पुलिस फुट पेट्रोलिंग (बीट पुलिसिंग) को प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी महिला बीट पुलिस अधिकारी गांवों और वार्डों में जाकर महिलाओं के साथ संवाद जागरूकता अभियान चलाएंगे। महिलाओं और बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, मातृ वंदना योजना, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम करके अधिक से अधिक नए लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार और आरंभिक पूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मील का पत्थर साबित होगा मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 'महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान' के उद्देश्यों के साथ 'मिशन शक्ति' के रूप में वृहद अभियान के पहले चरण की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी। अभी तक चार चरणों में इसका संचालन किया जा चुका है। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह सहित 28 सरकारी विभाग, समाजसेवी संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान हिस्सेदारी कर रहे हैं। अभियान के पहले चार चरणों में प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके नौ करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच कर उन्हें प्रदेश सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी है। मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। योगी सरकार ने अभियान को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक भागीदारी बढ़ाई है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं। इस अभियान की सफलता समाज के हर वर्ग की भागीदारी पर निर्भर करती है। अगर समाज की समस्त शक्तियाँ एकजुट हों, तो महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का सपना साकार किया जा सकता है, जिससे सुरक्षित, समान और समृद्ध प्रदेश की स्थापना संभव होगी। ◆

मो. : 9837099175
(लेखक पत्रकार हैं)

हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम

—पवन सिंह

उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो चुका है जो तेजी से हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन एनर्जी उत्पादन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान केन्द्रित कर चुकी है और इसके परिणाम जमीन पर भी उतरने आरंभ हो चुके हैं।

मिर्जापुर में बहुत तेजी से सौर ऊर्जा प्लांट लगाये जा रहे हैं जिनमें विजयपुर गांव का 75 मेगावॉट का प्लांट और दादर कलां गांव में 100 मेगावॉट का प्लांट काम कर रहे हैं। एक अन्य 100 मेगावॉट का प्लांट 200 हेक्टेयर जमीन पर 400 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा है। बनारस के शहंशाहपुर गांव स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ने काम करना आरंभ कर दिया है जो कि प्रतिदिन 3150 बायोगैस का उत्पादन करता है।

इसी क्रम में राज्य के जालौन, कानपुर देहात व कानपुर में सोलर पॉवर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से लग गये सौर ऊर्जा पॉवर प्लांटों से 6 हजार मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे को सोलर एक्सप्रेस वे में बदलने की योजना पर कार्य आरंभ हो चुका है जिससे 450 मेगावॉट सौर ऊर्जा मिलेगी। रूफटॉप सोलर ऊर्जा के तहत जुलाई, 2025 तक 27 हजार 771 रूफटॉप इंस्टॉलेशन कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ चुका है।

गोरखपुर में अगस्त, 2025 से राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ने काम करना आरंभ कर दिया है। जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 72 हजार टन है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक स्वच्छ नवीकरणीय उर्जा स्रोत है, जिसे पानी के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। इससे ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम या शून्य होता है।

उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5 हजार 157 मेगावॉट पहुंच चुकी है और यह जल्द ही 10 हजार मेगावॉट को छू लेगी।

मिर्जापुर में बहुत तेजी से सौर ऊर्जा प्लांट लगाये जा रहे हैं जिनमें विजयपुर गांव का 75 मेगावॉट का प्लांट और दादर कलां गांव में 100 मेगावॉट के प्लांट काम कर रहे हैं। एक अन्य 100 मेगावॉट का प्लांट 200 हेक्टेयर जमीन पर 400 करोड़ की लागत से लगाया जा रहा है। बनारस के शहंशाहपुर गांव स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ने काम करना आरंभ कर दिया है जो कि प्रतिदिन 3150 बायोगैस का उत्पादन करता है। इसके अलावा इस प्लांट की खासियत यह भी है कि यह तरल और ठोस उर्वरक का भी उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी जीबीसी प्लांट स्थापित हो चुके है जिनकी कुल क्षमता 213 टन प्रतिदिन है। यह संख्या भारत में सबसे अधिक है और देश के कुल सीबीजी संयंत्रों का लगभग 19 प्रतिशत है जबकि अभी 129 नये सीबाजी प्लांट निर्माणाधीन हैं। यानी कुछ ही सालों में सीबीजी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य अब पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की दिशा में कदम

रखने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य में 14 जिलों का सर्वे हो चुका है। सैटेलाइट सर्वे में 80 मीटर की उंचाई पर हवा की गति का अध्ययन किया गया है। इनमें ललितपुर के शंकरवर कला, मुजफ्फरपुर के निमराना, व बरेली के देवरनिया को ज्यादा उपयुक्त पाया गया है। यही नहीं राज्य सरकार अब यह प्रयास कर रही है कि छोटी–छोटी पनबिजली उत्पादन इकाइयां स्थापित हों। इसी दिशा में पूर्वांचल के सोनभद्र, चंदौली व मिर्जापुर में करीब 15 हजार करोड़ की लागत से पन बिजली संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कार्य प्रगति पर है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और 3250 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होगा। जिस तरह से राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी के विभिन्न आयामों पर कार्य कर रही है, वह कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर पहुंचा देगी। ◆

मो. : 8896122242

(लेखक वरिष्ठ फोटो पत्रकार हैं)

यूपी में अनवरत होते पुलिस सुधार

—उपेन्द्र कुमार

किसी भी राज्य की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था पहली शर्त होती है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के अभाव में राज्य यह तीनों ही आयाम प्राप्त करने में असफल दिखाई देने लगता है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए राज्य का पुलिस बल सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है और तब पुलिस सुधार की प्रासंगिकता के विषय में बात उठती है।सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह निर्णय (वर्ष 2006) ने राज्यों को महत्त्वपूर्ण सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल और कानून एवं व्यवस्था से जाँच को अलग करना शामिल है।

विगत 08 वर्षों में राज्य की सुदृढ़ कानून–व्यवस्था के परिणामस्वरूप प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह तथा जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है। इस कार्य के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचकर प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास कराया गया है। देश के अनेक राज्य मुख्यमंत्री की कार्यशैली का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया में इसे यू.पी. मॉडल के नाम से जाना जाता है।

प्रदेश में सुरक्षा के वातावरण तथा रूल ऑफ लॉ के परिणामस्वरूप यहां देश–विदेश का प्रत्येक व्यक्ति निवेश करने को तैयार है। ऐसा इसलिए सम्भव हो सका, क्योंकि निवेशकों को विश्वास है कि उनके साथ यहां किसी स्तर पर धोखा नहीं होगा। प्रदेश में आ रहा निवेश रोजगार का माध्यम बन रहा है। प्रदेश सरकार यहां के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का अच्छा व्यवहार केवल उसकी संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ह्यूमन इन्टेलिजेंस का भी माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त जनसामान्य की सूचनाओं से ह्यूमन इन्टेलिजेंस के माध्यम से जमीनी सच की जानकारी प्राप्त होती है। ह्यूमन इन्टेलिजेंस आज का सबसे बड़ा हथियार है, पुलिस इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर रही है।

थाना, सर्किल और पुलिस लाइन में बेहतर समन्वय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार व संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है, साथ ही, उसके मन में पुलिस के प्रति एक बेहतर धारणा भी बनती

है। विगत 09 वर्षों में न्यूनतम वर्ष 2017 से अब तक 02 लाख 19 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गयी है। इन्टरफेरेंस के साथ पुलिस को कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी जिले की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी के लिए टेन्योर में स्थिरता आवश्यक है।

प्रदेश सरकार ने पुलिस अधिकारियों के टेन्योर में स्थिरता प्रदान की है। एक पुलिस अधिकारी मिनिमम 02 वर्ष तक एक जिले व रेन्ज में अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर तीन–चार महीने में ही हो जाते थे। प्रदेश सरकार पुलिस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगातार वृद्धि कर रही है। पहले पुलिस के जवानों को खपरैल और एसबेस्टस बैरक में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज प्रदेश के अनेक जनपदों में हाईराइज बिल्डिंगों में आवास की व्यवस्था की गयी है। पहले 10 जनपद ऐसे थे, जहां दशकों से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थीं। प्रदेश सरकार ने वहां पर सुविधाओं में वृद्धि की है। पी.ए.सी. की जिन कम्पनियों को समाप्त किया गया था, उनका पुनर्गठन और महिला वाहिनियों का गठन किया गया। प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 13 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साइबर मुख्यालय, मॉडल थानों और आधुनिक संसाधनों से पुलिस को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है।वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम थाने संचालित हैं। जी.आर.पी. थाने सहित प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। साथ ही, साइबर क्राइम थाना लखनऊ में एडवान्स फॉरेंसिंक लैब की स्थापना भी की गयी है। साइबर हेल्पलाइन नम्बर–1930 पर प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए 238.26 करोड़ रुपये फ्रीज किये गये। साइबर अपराध में प्रयुक्त 20,094 मोबाइल नम्बर तथा 18,198 आई.एम.ई.आई. नम्बर ब्लॉक कराये गये। साई–ट्रेन के माध्यम से 84,705 पुलिस कर्मी प्रशिक्षित किये गये। साइबर विशेषज्ञों द्वारा 18,861 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2017 से 30 नवम्बर, 2025 तक दर्ज 87,175 पंजीकृत अभियोगों से से 74,824 का निस्तारण किया जा चुका है। 53,056 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है तथा 378 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बरामद की गयी है। लोगों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। आमजन एन.सी.आर.पी. पोर्टल व हेल्पलाइन नम्बर पर साइबर फ्रॉड से सम्बन्धित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

प्रदेश के सभी जनपदों में ई–ऑफिस व्यवस्था क्रियान्वित की जा चुकी है। 'मिशन कर्मयोगी' के माध्यम से केन्द्र, राज्य व स्थानीय लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को इसकी नोडल एजेन्सी बनाया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए 04 विशिष्ट कोर्स चलाए गए हैं। आई–गॉट पोर्टल पर प्रशिक्षण को वार्षिक मूल्यांकन से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश को पूरे देश में सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। यह पुलिस द्वारा विभिन्न नवाचारों को अपनाने व कार्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने डिजिटल कारागार, बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति, सुरक्षित बचपन योजना जैसी पहलों के माध्यम से कारागार व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। उत्तर प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है, जिसने कारागारों को उत्पादक इकाई के रूप में भी स्थापित किया। प्रदेश सरकार ने मॉडर्न जेल मैनुअल लागू किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन के कार्यों में तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आई.सी.जे.एस. पोर्टल के माध्यम से ई–प्रॉसीक्यूशन सम्पन्न किया जा रहा है। ई–रिपोर्टिंग, ई–कोर्ट्स, नवीन आपराधिक गतिविधियों का डैशबोर्ड जैसे नवाचार इनमें प्रमुख हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में 66 हजार से अधिक गवाही करायी गयी हैं। परिणामस्वरूप इस कार्य में व्यय धनराशि में भी कमी आयी है। प्रदेश पुलिस रीएक्टिव पुलिसिंग से बढ़कर प्रेडिक्टिव व प्रोएक्टिव पुलिसिंग की ओर बढ़ी है। सी.सी.टी.एन.एस. के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। विवेचनाओं की पेण्डेन्सी को कम करने में फॉरेन्सिक इन्वेस्टीगेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेन्सिक विज्ञान संस्थान को स्थापित किया है, जो सक्रियता से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में मात्र 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं (एफ.एस.एल.) थीं। वर्ष 2017 के बाद 08 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है तथा 06 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। सभी एफ.एस.एल. बेहतर ढंग से कार्य करें। राज्य सरकार ने सभी जनपदों में 02–02 फॉरेन्सिक लैब भी उपलब्ध करायी हैं। अतः स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश की कानून व्यवस्था नित नए आयाम स्थापित कर रही है। ◆

मो. : 6306959511

(लेखक मुख्यमंत्री सूचना परिसर में फीचर लेखक (सूचना अधिकारी) हैं)

महिला सशक्तीकरण अभियान
'उज्ज्वला' से बना ऊर्जावान

होली के शुभ अवसर पर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

स्वच्छ ईंधन..बेहतर जीवन !

के अंतर्गत

₹1,500 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के **1.86 करोड़** उज्ज्वला परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया

द्वारा

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

दिनांक : 28 फरवरी, 2026

धुएं से मुक्ति, हर घर समृद्धि ♦ होली और दीपावली पर नि:शुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा

♦ पात्र परिवारों को प्रति रिफिल केंद्र सरकार द्वारा ₹335.40 एवं राज्य सरकार द्वारा ₹559.58 की सब्सिडी अनुमन्य

♦ प्रथम चरण (अक्टूबर से दिसंबर, 2025) दीपावली पर तथा द्वितीय चरण (जनवरी से मार्च, 2026) होली पर रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले उज्ज्वला परिवार लाभान्वित

♦ महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति, स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण सुधार की ओर सार्थक कदम

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक–चन्द्र विजय वर्मा।